बहुजन हिताय! बहुजन सुखाय!

सक्षम भारत

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक | इन्द्रजीत सिंह, मुख्य संवाददाता/सचिव, CNSI-Delhi

दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से प्रसारित

www.sakshambharat;net, E-mail : saksham.bharat@hotmail.com

Member : CENTRAL NEWSPAPER SOCIETY OF INDIA DELHI

● वर्ष: 24 ● अंक: 07 ● नई दिल्ली ● शनिवार 11 अक्तूबर 2025 ● प्रभात कालीन ● मूल्य: 3 रूपया ● पृष्ठ: 4

रिपब्लिकन मजदूर संगठन के सदस्य बनें

E-mail : rmsdp@hotmail.com

अनागरिक गीता भारती भवन

बी-2/370, सुल्तानपुरी

दिल्ली-86

सीएम रेखा ने 11 कोरोना योद्धाओं के परिवारों को दिए एक करोड़ के चेक, पूर्व केजरीवाल सरकार पर कसा तंज

नई दिल्ली । दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शनिवार को 11 कोरोना योद्धाओं के परिवारों को एक करोड़ रुपये की राशि दी। सीएम ने कोविड-19 के दौरान मृतकों के परिवारों को चेक वितरण करने पर कहा कि इन लोगों के आवेदन वर्षों से पड़े थे। कोविड-19 के दौरान जब पूरी दुनिया अपने घरों में थी, तब भी ये लोगों को बचाने के लिए काम कर रहे थे। किसी सफाई कर्मचारी, डॉक्टर, नर्स ने छुट्टी नहीं ली, किसी ने मना नहीं किया, ऐसे में सरकार ने उन्हें उनका हक नहीं दिया। आगे कहा कि पिछली सरकार किस काम में लगी थी कि उन्हें कई साल तक याद नहीं आया कि उन्हें पैसे देने है... मैं इन सभी परिवारों से क्षमाप्रार्थी हूं, और आज हमने उनके हक का पैसा वितरित किया है।

दिल्ली में बीजेपी की महाबैठक, बिहार चुनाव को लेकर शाह-नड्डा वरिष्ठ नेताओं के साथ कर रहे मंथन

नई दिल्ली । बिहार विधानसभा चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) में बातचीत का दौर अब अंतिम चरण है। भाजपा और जदयू ने अपने कई पुराने चेहरों को हरी झंडी भी दे दी है। लेकिन, अब तक औपचारिक रूप से घोषणा नहीं की है। यह घोषणा आज शाम तक संभावित है। लेकिन, इससे पहले भारतीय जनता पार्टी की कोर कमेटी के सदस्य दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर जुटे हैं। गृह मंत्री अमित शाह, बिहार चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय राय मंत्री नित्यानंद राय समेत भाजपा के वरिष्ठ नेता सीट शेयरिंग समेत कई मुद्दों पर बातचीत कर रहे हैं। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) में सीट बंटवारे का काम 95 फीसदी तक हो चुका है। भाजपा और जदयू दोनों 100 से अधिक पर चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। केंद्रीय चिराग पासवान की पार्टी को 28, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी को आठ और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को करीब पांच सीटें भाजपा और जदयू देना चाहती है। लेकिन, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा मानने को तैयार नहीं। चिराग 35 से कम सीटों पर चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। वहीं जीतन राम मांझी का तर्क है कि राय स्तर की पार्टी बनने के लिए आठ विधायक चाहिए। हमारे पास पहले से चार विधायक हैं। ऐसे में 15 सीटों से कम पर चुनाव हमलोग नहीं लड़ कसते हैं। वहीं आरएलएसपी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने 24 सीटों की मांग की है। तीनों पार्टी के नेताओं ने चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान से मिलकर अपनी-अपनी बात रख दी है। जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने दावा किया है कि एनडीए के घटक दलों के कहीं कोई मतभेद नहीं है। सबलोग एकजुट हैं। जल्द ही सीट बंटवारे का एलान कर दिया जाएगा। बिहार चुनाव को लेकर बीजेपी के साथ सीट बंटवारे की बातचीत पर एलजेपी (रामविलास) के अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा कि बातचीत सकारात्मक ढंग से चल रही है और अब अपने अंतिम चरण में है। जिस घोषणा का इंतजार आपलोग कर रहे हैं, वह भी जल्द होने वाली है। हमलोग हर एक चीजों पर विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। ताकि बाद में गठबंधन के अंदर किसी भी चीजों को लेकर कोई संशय नहीं हो। हम हर छोटे-बड़े मुद्दे, सीटों, उम्मीदवारों और प्रचार को लेकर विस्तृत चर्चा कर रहे हैं। जहां पर मेरे प्रधानमंत्री हैं, वहां पर मुझे अपने सम्मान करने की चिंता नहीं है।

नई दिल्ली स्टेशन पर स्थायी सुविधा केंद्र तैयार : रेल मंत्री ने की समीक्षा, 76 स्टेशनों पर भी होगी लागू व्यवस्था

नई दिल्ली । रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बने नए होल्डिंग एरिया का निरीक्षण भी किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस नई व्यवस्था से यात्रियों को न केवल राहत मिलेगी, बल्कि स्टेशन की भीड़ प्रबंधन प्रणाली भी और बेहतर होगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की बढ़ती भीड़ को नियंत्रित करने और बेहतर अनुभव देने के लिए अब एक 'यात्री सुविधा केंद्र' तैयार किया गया है। रेल मंत्री मंत्री ने बताया कि दो साल पहले एक अस्थायी होल्डिंग एरिया का प्रयोग किया गया था, जिससे यात्रियों को काफी राहत मिली थी। अब उसी प्रयोग को स्थायी रूप में लागू किया गया है। यह सुविधा खास तौर पर उन यात्रियों के लिए है, जो बिना आरक्षण टिकट के स्टेशन पहुंचते हैं। रेल मंत्री ने बताया कि अब सभी टिकट काउंटर इस केंद्र में स्थानांतरित कर दिए गए हैं। अगर किसी यात्री के पास आरक्षित टिकट है, तो वह सीधे प्लेटफॉर्म की ओर जा सकता है। अगर टिकट नहीं है, तो वह यहां आकर आराम से टिकट खरीद सकता है और व्यवस्थित तरीके से प्रवेश कर सकता है। यह केंद्र यात्रियों को बैठने की बड़ी जगह, पर्याप्त शौचालय और आरामदायक माहौल प्रदान करेगा। रेल मंत्री ने कहा कि यह नई दिल्ली स्टेशन के लिए स्थायी सुविधा है, ताकि यात्रियों को प्लेटफॉर्म पर भीड़ का सामना न करना पड़े। रेल मंत्री ने बताया कि देशभर के 76 प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर, जहां भीड़ अधिक रहती है, इसी तरह की स्थायी व्यवस्था लागू की जाएगी। आने वाले समय में, जब छठ और दीपावली जैसे त्योहारों पर यात्रियों की भारी भीड़ उमड़ेगी, तब इस नई प्रणाली की व्यावहारिक परीक्षा होगी। उस अनुभव के आधार पर अन्य स्टेशनों पर भी ऐसी सुविधाएं विकसित की जाएंगी। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि रेल मंत्रालय लगातार यात्री सुविधाओं को एक नए स्तर तक पहुंचाने के प्रयास में जुटा है। उन्होंने बताया कि आने वाले फरवरी या मार्च तक आईआरसीटीसी (इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन) की क्षमता करीब दस गुना बढ़ जाएगी। साथ ही, यात्रियों में रेल वन ऐप को लेकर भी रुझान तेजी से बढ़ रहा है। मंत्री ने कहा, हम हर तरह की प्रतिक्रिया को गंभीरता से लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देशभर में रेलवे के ढांचे को नए रूप में विकसित किया जा रहा है।

जातिगत टिप्पणी को लेकर सोहना बस स्टैंड पर दो पक्ष भिड़े, चार लोग घायल

सोहना। सोहना बस स्टैंड पर शनिवार सुबह अपशब्द कहने को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया।इसमें होमगार्ड, ला छात्र सहित चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मारपीट में ला छात्र की टांग टूट गई। घटना के बाद सभी आरोपित मौके से फरार हो गए। घायलों को सोहना के नागरिक अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें गुरुग्राम रेफर कर दिया गया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पीड़ित आबिद ने बताया कि वह दिल्ली में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं।प्रतिदिन रोडवेज बस से ड्यूटी के लिए आते जाते हैं।शनिवार सुबह जब वह सोहना बस स्टैंड से बस में चढ़ रहे थे, तभी पास खड़े एक युवक ने जाति को लेकर अपशब्द टिप्पणी की। इस बात पर दोनों के बीच बहस शुरू हो गई। विवाद बढ़ने पर आबिद ने अपने भाई जुबेर को मौके पर बुला लिया। जुबेर होमगार्ड के पद पर कार्यरत है। टिप्पणी करने वाले दूसरे पक्ष के युवक ने भी अपने पांच-छह साथियों को बुला लिया। उनके साथी लाठी-डंडों से लैस होकर आए और आबिद व जुबैर पर हमला कर दिया।

सीजेआई बोले- डिजिटल दौर में बालिका सुरक्षा पर चिंता, विशेष कानून-प्रशिक्षण को जरूरी बताया

नई दिल्ली। चीफ जस्टिस (सीजेआई) बीआर गवई ने डिजिटल युग में लड़कियों की सुरक्षा पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन उत्पीड़न, साइबर हमलों, डिजिटल माध्यम से पीछा करने, व्यक्तिगत डाटा के दुरुपयोग और डीपफेक तस्वीरों जैसी समस्याओं के कारण लड़कियां गंभीर रूप से असुरक्षित हैं। उन्होंने कानून एवं प्रवर्तन एजेंसियों और नीति निर्धारकों के लिए विशेष कानून और प्रशिक्षण की आवश्यकता पर जोर दिया। सीजेआई बालिकाओं की सुरक्षा भारत में उसके लिए एक सुरक्षित और सक्षम वातावरण की ओर विषय पर आयोजित राष्ट्रीय वार्षिक हितधारक परामर्श बैठक को संबोधित कर रहे थे।

यह कार्यक्रम सुप्रीम कोर्ट की किशोर न्याय समिति (जेजेसी) के तत्वावधान में यूनिसेफ इंडिया के सहयोग से आयोजित किया गया था। उन्होंने कहा कि संविधान और कानूनी संरक्षण के बावजूद देश की कई बालिकाओं को अब भी दुर्भाग्य से उनके मौलिक अधिकारों और यहां तक कि जीवित रहने के लिए जरूरी बुनियादी जरूरतों से वंचित रखा जाता है। यह असुरक्षा उन्हें यौन शोषण, उत्पीड़न और अन्य हानिकारक प्रथाओं जैसे कि महिलाओं के शरीर के अंगों को चोट पहुंचाना, कुपोषण, लिंग का चयन कर गर्भपात, तस्करी और उनकी मर्जी के खिलाफ बाल विवाह के अधिक जोखिम में डाल देती है। जस्टिस गवई ने आगे कहा, उनकी (बालिकाओं) सुरक्षा केवल उसके शरीर की रक्षा करना नहीं है, बल्कि उनकी आत्मा को आजाद करना भी है। एक ऐसा समाज बनाना है जहां वह गरिमा के साथ सिर ऊंचा करके खड़ी हो सके और जहां उसकी आकांक्षाएं शिक्षा और समानता से पोषित हों... हमें उन गहरी जड़ें जमा चुकी पितृसत्तात्मक रीति-रिवाजों का सामना करना होगा और उन्हें दूर करना होगा, जो लड़कियों को उनका सही स्थान देने से रोकते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर की कविता व्हेयर द माइंड इज विदाउट फियर को याद करते हुए सीजेआई ने कहा कि यह कविता उस भावना को पूरी तरह से व्यक्त करती है, जिसे बालिका की सुरक्षा के लिए हासिल करना जरूरी है। उन्होंने कहा, यह सपना अधूरा रहेगा, जब तक हमारे देश की कोई भी लड़की डर के साए में रहे।

सोनिया गांधी ने पूरन की पत्नी को लिखी चिट्ठी, कहा- सत्ता में बैठे लोगों का पक्षपातपूर्ण रवैया

नई दिल्ली । कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार की पत्नी वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अमनीत पी. कुमार को पत्र लिखा है। पत्र में कहा है कि उनके पति की मृत्यु इस बात की याद दिलाती है कि सत्ता में बैठे लोगों का पक्षपातपूर्ण और पूर्वाग्रह से भरा रवैया आज भी सबसे वरिष्ठ अधिकारियों को सामाजिक न्याय से वंचित कर देता है। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अपने पत्र में कहा कि वह और देश के करोड़ों लोग अमनीत पी. कुमार के साथ न्याय की इस राह में खड़े हैं। पूरन कुमार 2001 बैच के भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी थे, जिन्होंने कथित रूप से मंगलवार को चंडीगढ़ सेक्टर-11 स्थित अपने आवास पर खुद को गोली मार ली थी। उनकी पत्नी अमनीत पी. कुमार हरियाणा सरकार में आयुक्त और सचिव पद पर कार्यरत हैं। सोनिया गांधी ने पत्र में लिखा, आपके पति और वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी श्री वाई. पूरन कुमार की दुखद मृत्यु की खबर अत्यंत चौंकाने वाली और गहरी पीड़ा देने वाली है। इस कठिन समय में मैं आपको और आपके पूरे परिवार को अपनी संवेदनाएं प्रेषित करती हूं। उन्होंने आगे कहा, श्री वाई. पूरन कुमार का जाना हमें यह याद दिलाता है कि आज भी सत्ता में बैठे लोगों का पूर्वाग्रहपूर्ण और पक्षपात भरा रवैया, वरिष्ठतम अधिकारियों को भी सामाजिक न्याय से वंचित कर देता है। मैं और देश के करोड़ों लोग न्याय की इस राह में आपके साथ हैं। सोनिया गांधी ने पत्र के अंत में लिखा, ईश्वर आपको इस कठिन परिस्थिति में धैर्य, साहस और शक्ति प्रदान करे। इस बीच, चंडीगढ़ पुलिस ने शुक्रवार को इस कथित आत्महत्या मामले की जांच के लिए छह सदस्यीय विशेष जांच दल का गठन किया है। हालांकि, कुमार के परिवार ने अब तक पोस्टमॉर्टम की अनुमति नहीं दी है। उनकी पत्नी ने एफआईआर में दर्ज अधूरी जानकारी पर सवाल उठाया है। पूरन कुमार हाल ही में रोहतक के सुनारिया स्थित पुलिस प्रशिक्षण केंद्र में पुलिस महानिरीक्षक के रूप में तैनात थे। उन्होंने अपने पीछे आठ पन्नों का एक कथित अंतिम नोट छोड़ा है, जिसमें उन्होंने आठ वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों के नाम लिए हैं, जिनमें हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर और रोहतक एसपी नरेंद्र बिजारणिया शामिल हैं। इस नोट में उन्होंने पिछले कुछ वर्षों में झेली गई मानसिक प्रताड़ना और अपमान का विवरण लिखा है।

दिवाली पर पटाखे- हां या ना? सुप्रीम कोर्ट में इस बार पूरा मामला ही पलट जाएगा

नई दिल्ली। आपने पिछले कुछ सालों से ये देखा होगा कि जैसे ही दिवाली का त्यौहार आता है पटाखों के खिलाफ एक नई मुहिम शुरू हो जाती है। कहा जाता है कि पटाखों को फोड़ने से प्रदूषण बढ़ जाएगा। एक स्लोगन आम तौर पर दिख जाएगा Say No to crackers यानी दिवाली पर पटाखों का इस्तेमाल न करें। स्कूलों में इस तरह का ड्राइंग बनवाई जाती है और इसे बढ़ चढ़कर प्रचारित भी किया जाता है। हालांकि जिस तरह का प्रदूषण का इतिहास दिल्ली का रहा है। कई लोग इसे सही भी मानते हैं। प्रदूषण का स्तर पहले से ही इतना खराब है तो उसमें ये भी जुड़ जाए तो कई लोगों के लिए मुश्किल पैदा कर सकता है। लेकिन Say No to crackers वाली मुहिम से बहुत सारे लोगों के मन में दिवाली के प्रति ऐसी छवि बनाने की कोशिश की जा रही है कि दिवाली का त्यौहार प्रदूषण लाता है। दिवाली पर पटाखें फोड़ने से हवा जहरीली हो जाती है। हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट में पटाखों को लेकर सुनवाई हुई है। देश की सर्वोच्च अदालत ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है। जिसके बाद से कहा जा रहा है कि क्या बीजेपी के राज में इस बार दिल्ली की दीवाली पटाखे वाली होगी? दिल्लीवालों के मन में अभी से ही पटाखें छूट रहे हैं। इस बार दिवाली और कुछ अन्य मौकों पर उन्हें ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति मिल सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिए कि दिल्ली-एनसी आर में दिवाली और अन्य त्योहारों के दौरान कुछ शर्तों के साथ ग्रीन पटाखों के इस्तेमाल की अनुमति दी जा सकती है। इस मामले में सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि दिल्ली-एनसीआर में पटाखे फोड़ने पर पूर्ण प्रतिबंध न तो व्यवहारिक है और न ही आदर्श। अदालत ने कहा कि प्रतिबंधों का बार-बार उल्लंघन होता है, इसलिए पर्यावरण सुरक्षा और लोगों की आजीविका, दोनों के बीच संतुलन बनाना जरूरी है। सुनवाई के दौरान केंद्र और एनसीआर रायों की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पटाखों पर समय सीमा हटाने की मांग की। उन्होंने कहा कि बच्चों को त्योहारों पर उत्सव मनाने की पूरी अनुमति मिलनी चाहिए। इस पर चीफ जस्टिस ने मौखिक टिप्पणी में कहा कि फिलहाल हम दिवाली के दौरान कुछ हद तक प्रतिबंध में ढील देने पर विचार कर रहे हैं। चीफ जस्टिस गवई ने सवाल किया कि क्या 2018 में प्रतिबंध के बाद दिल्ली-एनसीआर की वायु गुणवत्ता में सुधार हुआ या वह और खराब हुई? इस पर सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि आंकड़ों के अनुसार वायु गुणवत्ता लगभग समान रही है। सीजेआई ने कहा कि कुछ क्षेत्रों में दिवाली सुबह (चतुर्दशी) को मनाई जाती है, इसलिए उस समय को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। उन्होंने 2018 के अर्जुन गोपाल बनाम भारत सरकार फैसले की समीक्षा करने की संभावना जताई। दरअसल, उस फैसले में ग्रीन पटाखे को इजाजत दी गई थी। चीफ जस्टिस ने टिप्पणी में कहा कि हम इसे कैलेंस करने की कोशिश करेंगे। ग्रीन पटाखें उन्हें कहा जाता है दो पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचाते हैं और जिनसे कम प्रदूषण होता है। नेशनल इनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के दावे के अनुसार इन पटाखों में समान्य पटाखों के मुकाबले केमिकल्स नहीं होते हैं। सामान्य पटाखें दो से तीन दिन तक हवा को जहरीला रखते हैं। जबकि ग्रीन पटाखों में धुआं, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड 30 फीसदी कम निकलता है और इनके सीमित इस्तेमाल से यादा वायु प्रदूषण नहीं फैलता और इससे ध्वनि प्रदूषण भी कम होता है। सामान्य पटाखों का शोर 160 डेसिबल तक होता है जबकि ग्रीन पटाखों का शोर 110 से 125 डेसिबल तक होता है।

सबसे बड़ी बात ये है कि ग्रीन पटाखें 30 सेकेंड से यादा नहीं चलते। जबकि सामान्य पटाखें इससे कहीं यादा देर तक चलते हैं और प्रदूषण भी यादा फैलाते हैं। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि दिल्ली में दीपावली के दौरान पटाखों पर प्रतिबंध जारी रखने या जलाने की छूट को लेकर सुप्रीम कोर्ट का जो भी आदेश आएगा, आम आदमी पार्टी उसका स्वागत करेगी। पार्टी के दिल्ली प्रदेश संयोजक सौरभ भारद्वाज ने कहा कि आप सरकार के दौरान यमुना किनारे छठ पूजा मनाने और दिवाली पर पटाखे जलाने को लेकर कोर्ट से जो आदेश आते थे, उसका हम पालन करते थे। अब अगर कोर्ट कहता है कि कि कितना भी प्रदूषण हो, लेकिन दिवाली पर पटाखे जलने चाहिए तो हम भी उसे मान लेंगे। वहीं, आप की ओर से आए बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है कि आप ने जान बूझकर एक समुदाय विशेष को खुश करने के लिए न्यायालयों में ऐसी पर्यावरण रिपोर्ट दर्ज करवाई, जिनके चलते रोक लगी रहे।

भारत-ब्रिटेन : नया युग शुरू

अंग्रेजों ने भारत पर 200 वर्षों तक शासन किया और भारत की सम्पदा को लूटा। औपनिवेशिक अतीत का दबाव, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अंग्रेजी शासन के अत्याचारों और गुलामी के दर्दनाक अनुभवों के चलते भारत-ब्रिटेन संबंध वर्षों तक संवेदनशील बने रहे। दोनों देशों के रिश्तों की जटिलता की कहानी बहुत लम्बी है। अब जबकि वैश्विक समीकरण तेजी से बदल रहे हैं तो दोनों देश संबंधों की नई परिभाषा गढ़ रहे हैं। यह परिभाषा न केवल कूटनीतिक जटिलता बल्कि रणनीतिक और आर्थिक पहलुओं के दृष्टिगत निर्णायक है। एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ व्यापार युद्ध बढ़ा रहा है तो दूसरी तरफ ब्रिटेन अपनी अर्थव्यवस्था को खस्ता हालत से बाहर निकालने के लिए नए कदम उठा रहा है। भारत भी ट्रंप के टैरिफ के प्रभाव को कम करने के लिए नए बाजारों की तलाश कर रहा है। इन परिस्थितियों के बीच ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीरस्टार्मर की भारत यात्रा ने दोनों देशों के रिश्तों को नया मोड़ दे दिया है। इस दौर का उद्देश्य भारत-ब्रिटेन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को अंतिम रूप देना और जुलाई 2026 तक इसे लागू करने की दिशा में ठोस प्रगति करना था। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और कीर स्टार्मर की बातचीत में दोनों नेताओं में व्यापार, टैक्नोलॉजी, डिफेंस और शिक्षा भागीदारी जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर सहमति बनी। भारत को ब्रिटेन से 350 मिलियन पाउंड यानि 468 मिलियन डालर कीमत की मिसाइलों की सप्लाई के समझौते पर मुहर लगाई गई जो दोनों देशों की रक्षा साझेदारी को नई दिशा देगा। ब्रिटेन के 9 विश्वविद्यालय भारत के विश्वविद्यालयों में अपने कैम्पस खोलेंगे, जिससे भारत के छात्रों को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। जुलाई से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लागू होने से दोनों को बहुत फायदा होगा। ब्रिटेन से भारत आने वाले सामानों पर आयात टैरिफ 15 फीसदी से घटकर 3 फीसदी रह जाएगा। वहीं भारत से ब्रिटेन जाने वाले 99 फीसदी उत्पादों पर टैरिफ पूरी तरह खत्म हो जाएगा। ब्रेक्सिट के बाद यूरोपीय संघ से बाहर आने के बाद ब्रिटेन में अर्थव्यवस्था में मंदी का दौर चला। महंगाई, कमजोर उत्पादकता और वैश्विक आर्थिक झटकों जैसे महामारी और युद्धों के कारण उसकी अर्थव्यवस्था चुनौतियों का सामना कर रही है।

जबकि भारत की अर्थव्यवस्था ब्रिटेन से आगे निकल चुकी है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप अपने देश के दरवाजे बंद करते जा रहे हैं तो दूसरी तरफ ब्रिटेन कह रहा है-हमारे देश में आइए, हम प्रतिभाओं का स्वागत करते हैं। ऐसे में सवाल यह है कि भारत किसके साथ चलेगा? दुनिया के बदलते ट्रेड समीकरणों में भारत अब सिर्फ खेल का हिस्सा नहीं, बल्कि एक रणनीतिक खिलाड़ी बनता दिख रहा है। यूएस के टैरिफ हमलों के बीच भारत-यूके ट्रेड डील एक स्मार्ट चाल साबित हो सकती है। अमेरिका ने बेतहाशा टैरिफ बढ़ाए हैं, लेकिन क्या ब्रिटेन का नया व्यापार समझौता भारत के लिए सेफ्टी नेट बन सकता है? जब एक तरफ वॉशिंगटन से व्यापार युद्ध के बादल उठ रहे हैं, तो वहीं लंदन भारत को नया आर्थिक रास्ता दे रहा है। क्या यूके से हो रही ये डील भारत की एक्सपोर्ट इकोनॉमी को संभाले रखेगी? भारत के निर्यात क्षेत्र पर अमेरिकी टैरिफ का झटका साफ दिख रहा है। ट्रंप प्रशासन के नए टैरिफ स्ट्रक्चर ने भारत के लेबर इंटेंसिव सैक्टर्स जैसे टेक्सटाइल्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, इंजीनियरिंग गुड्स को सबसे ज्यादा प्रभावित किया है। अमेरिका के बढ़े टैरिफ शुल्क की वजह से भारत को हर साल करीब 40 अरब डॉलर के एक्सपोर्ट लॉस का सामना करना पड़ सकता है। इधर, वियतनाम, बंगलादेश और यहां तक कि चीन को फिलहाल कम टैरिफ मिल रहा है, यानी भारत की प्रतिस्पर्धा और कठिन हो गई है। ब्रिटेन हर साल करीब 27 अरब डॉलर के टेक्सटाइल उत्पाद आयात करता है, और 2024 में भारत का ब्रिटेन को निर्यात 13.5 अरब डॉलर था। यानि अब यह अंतर घट सकता है। इसके अलावा, भारत को यूके से लगभग 90% वस्तुओं पर टैरिफ-फ्री एक्सेस मिलेगा-जिनमें ज्वेलरी, फार्मा, इंजीनियरिंग और मशीनरी जैसे सेक्टर शामिल हैं। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन (एफआईईओ) के अध्यक्ष एस. सी. रल्हन ने एक बयान में इस समझौते को इंडियन एक्सपोर्टर्स के लिए एक परिवर्तनकारी क्षण बताते हुए कहा था कि यह समझौता प्रमुख क्षेत्रों, विशेष रूप से एमएसएमई सेक्टर और लेबर से जुड़े उद्योगों के लिए अभूतपूर्व अवसर प्रदान करता है। भारत-यूके डील का सबसे बड़ा फायदा सर्विस सेक्टर को होगा। ब्रिटिश बैंकिंग और इंश्योरेंस फर्म्स को भारत में निवेश का आसान रास्ता मिलेगा, वहीं भारतीय आईटी कंपनियों और कंसल्टिंग सर्विसेज को ब्रिटिश मार्केट में प्रवेश आसान होगा। इसके साथ-साथ, वीजा व्यवस्था भी इस डील का हिस्सा है। एक प्रस्तावित प्रावधान के तहत, भारत के स्किल्ड प्रोफेशनल्स को बिना किसी लंबी इमिग्रेशन प्रक्रिया के ब्रिटेन में शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स और टेक असाइनमेंट्स पर काम करने की इजाजत होगी। ब्रिटिश हायरिंग एजेंसी ग्लोबल टैलेंट ग्रुप के सीईओ साइमन हैरोल्ड ने कहा- भारत के पास स्किल है, हमारे पास स्कोप है। यह साझेदारी दोनों को फायदा पहुंचाएगी। तो क्या ब्रिटेन के साथ यह समझौता भारत को अमेरिकी आर्थिक अस्थिरता से बचा सकेगा? या फिर यह भी सिर्फ एक सीमित राहत साबित होगी? साफ है कि भारत अब एक ही बाजार पर निर्भर नहीं रहना चाहता और शायद यही रणनीति भारत को आने वाले दशक की आर्थिक कहानी में सबसे अलग बनाएगी। ब्रिटेन में लगभग 20 लाख से अधिक भारतीय मूल के लोग रहते हैं। राजनीति से लेकर व्यवसाय और शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य तक भारतीय ब्रिटेन की जीवनधारा से गहराई से जुड़े हैं। भारत अब ब्रिटेन के लिए स्वाभाविक विकल्प बन चुका है। वहीं भारत का ब्रिटेन ऐसा मित्र देश है जिसके माध्यम से वह यूरोप ही नहीं बल्कि पूरे अटलांटिक विश्व तक पहुंच बना सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप तो देखते ही रह गए और ब्रिटेन-भारत की दोस्ती परवान चढ़ गई। भविष्य में दोनों देशों की साझेदारी और मजबूत होगी और दोनों चुनौतियों का डटकर मुकाबला कर सकेंगे।

सम्पादकीय...

एनडीए के लिए शर्मिंदगी का सबब बने सम्राट

बिहार के उपमुख्यमंत्री और भाजपा नेता सम्राट चौधरी एनडीए के लिए काफी शर्मिंदगी का सबब साबित हो रहे हैं। न सिर्फ बड़बोलेपन के लिए जाने जाते हैं, बल्कि यह भी पता चला है कि वे अपनी शैक्षणिक योग्यताओं में भी हेराफेरी कर रहे हैं। 2010 में जब उन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव लड़ा था, तब उन्होंने चुनाव आयोग को दिए हलफनामे में खुद को सातवीं कक्षा पास बताया था। अब 15 साल बाद, उन्होंने खुद को कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय से पीएचडी बताया है। यह विसंगति राज्य में एक विवाद का विषय बन गई है और जन सुराज नेता प्रशांत किशोर ने चौधरी से उनकी अमेरिकी डॉक्टरेट की डिग्री का प्रमाण पेश करने की मांग की है। दरअसल, चौधरी के अपने एनडीए सहयोगी इस बढ़ते विवाद से स्तब्ध हैं और भाजपा प्रवक्ता और पूर्व केंद्रीय मंत्री आर. के. सिंह भी उनकी शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण की मांग में शामिल हो गए हैं। हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आर. के. सिंह ने कहा कि अगर चौधरी अपना पीएचडी प्रमाणपत्र नहीं दिखा सकते, तो कम से कम उन्हें मैट्रिक (दसवीं कक्षा) पास होने का प्रमाण पत्र तो पेश करना चाहिए। हालांकि बिहार में उनकी शैक्षणिक योग्यता पर सवाल उठ रहे हैं, चौधरी चुप हैं। चुनाव आयोग भी चुप है। केजरीवाल लुटियन दिल्ली के कुलीन वर्ग में शामिल आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल लुटियन दिल्ली के निवासियों के कुलीन वर्ग में शामिल हो गए हैं। उन्हें राजधानी के लोधी एस्टेट इलाके में एक बंगला आवंटित किया गया है, जहां देश के जाने-माने लोग रहते हैं। हालांकि उन्होंने खुद को एक आम आदमी के रूप में पहचान दिलाकर अपना राजनीतिक करियर बनाया, लेकिन इस साल के विधानसभा चुनावों में उनकी हार ने उन्हें एक खास आदमी बना दिया है। वे लुटियन दिल्ली में एक सरकारी बंगले के लिए इतने बेताब थे कि उनकी पार्टी ने एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल के अध्यक्ष के रूप में उन्हें आधिकारिक आवास आवंटित करने में हो रही अत्यधिक देरी के विरोध में दिल्ली उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की। अदालत के आदेश के बाद, केन्द्र सरकार आखिरकार मान गई। केजरीवाल वह बंगला चाहते थे जो पहले बसपा प्रमुख मायावती सांसद के रूप में लेती थीं, लेकिन उन्हें निराशा हुई जब शहरी विकास मंत्रालय ने उन्हें लोधी एस्टेट में एक बंगला दे दिया। लुटियन दिल्ली का बंगला जोन देश के सत्ताधारी वर्ग के बीच अपने विशाल आवासों, हरे-भरे लॉन और 24x7 उच्च श्रेणी की सुरक्षा के लिए बेहद लोकप्रिय है। ऐसा लगता है कि केजरीवाल ने इस विशिष्ट क्लब में शामिल होकर आम आदमी होने का सारा दिखावा छोड़ दिया है।

लगातार जहर उगल रहा है दक्षिणपंथी तंत्र यह एक दुखद दिन है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई पर हुए हालिया हमले की निंदा करने के बाद भी दक्षिणपंथी तंत्र लगातार जहर उगल रहा है। एक सनातन धर्म अनुयायी द्वारा खुली अदालत में मुख्य न्यायाधीश पर जूता फेंकने की घटना के तुरंत बाद, मोदी ने एक्स पर ट्वीट करके इस हमले को निंदनीय बताया और यहां तक कि हमले पर गवई की शांत और संयमित प्रतिक्रिया के लिए उनकी सराहना व्यक्त करने के लिए उन्हें फोन भी किया। दक्षिणपंथी ट्रोल्स पर ज्यादा असर नहीं हुआ, जिन्होंने सोशल मीडिया पर निंदनीय जातिवादी ट्वीट और मीम्स की बाढ़ ला दी। ऐसे ही एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) जनित वीडियो में दलितों के सदियों पुराने अपमान को दर्शाया गया है, जिन्हें उचित निपटान के लिए अपने सिर पर मिट्टी के बर्तन में मल ढोने के लिए मजबूर किया जाता था। यह आश्चर्यजनक है कि इन ट्रोल्स को बंद करने या एक्स पर उनके खातों को ब्लॉक करने का कोई प्रयास नहीं किया गया है, जो कि दूसरी तरफ के राजनीतिक विरोधियों द्वारा आपत्तिजनक ट्वीट्स का मानक आधिकारिक जवाब है। इसका श्रेय मुख्य न्यायाधीश को जाता है कि उन्होंने अदालत की अवमानना का नोटिस जारी करके या जूता फेंकने वाले के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की मांग करके विवाद को नहीं बढ़ाया। वास्तव में, हालांकि आरोपी को गिरफ्तार किया गया था, उसे कुछ ही घंटों में छोड़ दिया गया। नीतीश को 'मौका' मिल गया यह दिलचस्प है कि चुनाव आयोग ने बिहार चुनाव की तारीखों की घोषणा के लिए मंगलवार शाम 4 बजे अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस निर्धारित की। उससे ठीक एक घंटे पहले, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार के साथ साझेदारी में सितंबर में शुरू की गई महिला रोजगार योजना के तहत राज्य की 25 लाख महिलाओं को 10,000 रुपये की राशि हस्तांतरित की। तारीखों की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है। चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद नकद हस्तांतरण संभव नहीं होता। बेशक, विपक्ष ने सत्तारूढ़ एनडीए पर हमला बोला है और उस पर चुनाव आयोग के साथ छेड़छाड़ करके अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस इस तरह से तय करने का आरोप लगाया है कि नीतीश कुमार को नकद हस्तांतरण को मंजूरी देने के लिए पर्याप्त समय मिल जाए। महायुति में एक महायुद्ध महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ महायुति में एक महायुद्ध छिड़ता दिख रहा है, जहां मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अपने पूर्ववर्ती और सहयोगी सुशील कुमार शिंदे द्वारा शुरू की गई सभी कल्याणकारी योजनाओं को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। जाहिर है, वह लोकप्रिय लड़की बहन योजना के लिए संसाधन हस्तांतरित करने की योजना बना रहे हैं, जिसके बारे में भाजपा का मानना है कि इसी योजना ने महायुति को चुनाव जिताया था। दिलचस्प बात यह है कि फडणवीस ने लड़की बहन योजना को अपनी योजना बनाने का फैसला कर लिया है। यह उनके और शिंदे के बीच टकराव का एक और मुद्दा है, जिन्हें लगता है कि चुनाव जीतने वाली योजना का विचार उनका ही था।

राजनीति की 'प्रयोगशाला' बिहार

बिहार भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसके लोग पूरे देश में सर्वाधिक गरीब लोगों में गिने जाते हैं, मगर राजनीतिक रूप से सर्वाधिक धनी माने जाते हैं। यही वजह है कि इसकी धरती को राजनीतिक प्रयोगों की धरती कहा जाता है, हालांकि 80 के दशक तक इस राज्य में कांग्रेस का बोलबाला रहा, मगर बीच में सत्तर के दशक में यह समाजवाद की प्रयोगशाला भी बना जिसकी अलम्बरदारी जन नायक भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर कर रहे थे। स्व. ठाकुर जाति से नाई थे और उन्हें अपने गरीब होने, या जाति से नाई होने पर कोई अफसोस नहीं था बल्कि अपने इसी गुण की वजह से वह पूरे देश में राष्ट्रीय स्तर पर गरीबों के बीच पहचाने भी गये। उनका सबसे बड़ा योगदान यह था कि उन्होंने बिहार में धर्म या मजहब के नाम पर की जाने वाली राजनीति को हिन्दू-मुसलमानों के बीच प्रवेश नहीं करने दिया और गरीबों का ध्यान हमेशा आर्थिक मुद्दों पर ही केन्द्रित रखा। उनकी इस राजनीति से राज्य में कम्युनिस्टों का प्रभाव निरन्तर गिरता रहा वरना 1962 तक बिहार की प्रमुख विपक्षी पार्टी भारत की कम्युनिस्ट पार्टी हुआ करती थी। समाजवादी चिन्तक व जन नेता स्व. डा. राम मनोहर लोहिया के वह परम सहयोगी थे और समाजवादी विचारों के महान पोषक थे। वह पिछड़े समाज की एकजुटता के प्रबल समर्थक थे। जिसे उन्होंने 1974 में अपनी संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के स्व. चौधरी चरण सिंह की पार्टी भारतीय लोकदल में विलय के बाद पुष्ट किया और चौधरी साहब को अपना राष्ट्रीय नेता माना। चौधरी चरण सिंह ने सत्तर के दशक में पूरे उत्तर भारत में ग्रामीण मतदाताओं का सकल वोट बैंक बनाकर न केवल कांग्रेस के समक्ष बड़ा संकट खड़ा कर दिया था, बल्कि विपक्षी पार्टी जनसंघ को भी हैरत में डाल दिया था। 1967 में उनकी पार्टी के उदय के बाद उत्तर भारत में जनसंघ की बढ़त अवरुद्ध हो चुकी थी। इसका प्रमाण यह है कि 1967 में जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हुए तो इस संयुक्त राज्य की विधानसभा में जनसंघ (भाजपा) को कुल 101 सीटें प्राप्त हुईं, मगर जब 1969 में मध्यावधि चुनाव हुए जनसंघ को केवल 49 सीटें ही प्राप्त हो हुईं जबकि चौधरी साहब की नवोदित पार्टी भारतीय क्रान्ति दल को 117 सीटें प्राप्त हुईं। 1969 में बिहार में भी मध्यावधि चुनाव हुए थे। उस समय तक भारतीय क्रान्ति दल केवल उत्तर प्रदेश की ही पार्टी थी और बिहार में कर्पूरी ठाकुर की संसोपा का नम्बर दूसरा था। 1974 में इन दोनों पार्टियों का विलय हुआ था। इसके बाद बिहार की राजनीति में टकराव लगभग समाप्त सा होता गया और कांग्रेस का वर्चस्व समाप्त सा होता गया, हालांकि 1971 में राष्ट्रीय स्तर पर स्व. इन्दिरा गांधी की कांग्रेस पार्टी की तूफानी जीत ने एक बार फिर बिहार को कांग्रेस की झोली में डाल दिया था। कांग्रेस का यह दौर 1977 में तब जाकर टूटा जब इमरजेंसी के बाद लोकसभा चुनाव हुए और इसमें श्रीमती गांधी अपना लोकसभा चुनाव तक हार गईं, परन्तु इसके बाद 1980 में पुनः हुए लोकसभा चुनाव में इन्दिरा जी के सत्ता में वापस लौट आने पर बिहार में सत्ता पलट हुआ और कांग्रेस 1989 तक इस राज्य में निष्कंटक राज करती रही।

इस वर्ष हुए विधानसभा चुनावों में स्व. वी.पी. सिंह के जनता दल ने बाजी मारी, किन्तु इसे पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हुआ। तत्कालीन जनता दल नेता स्व. देवी लाल ने दिल्ली में संसद का चुनाव जीत कर श्री लालू प्रसाद यादव को बिहार विधायक दल का नेता बनाया और इस प्रकार लालू जी पहली बार बिहार के मुख्यमन्त्री बने। उस समय बिहार की भारतीय जनता पार्टी ने लालू जी को अपना समर्थन देने की घोषणा की थी। इसके बाद लालू जी व उनकी पत्नी 2005 तक राज्य के मुख्यमन्त्री रहे (केवल कुछ समय को छोड़कर), मगर तब तक जनता दल कई गुटों में विभक्त हो चुका था और 1974 के जेपी आन्दोलन से राजनीति में प्रवेश करने वाले वर्तमान मुख्यमन्त्री नीतीश कुमार स्व. जार्ज फर्नांडीज की अगुवाई में अपनी अलग समता पार्टी बना चुके थे, जबकि लालू जी ने अपनी पार्टी का नाम राष्ट्रीय जनता दल रख लिया था, वहीं इन दोनों में सबसे वरिष्ठ रहे स्व. राम विलास पासवान ने भी जनता दल से टूटकर अपनी अलग लोक जनशक्ति पार्टी बना ली थी। इस प्रकार ये तीनों बिहारी नेता अलग-अलग पार्टियों के सुप्रीमो के तौर पर सामने आये और तीनों ने स्व. चौधरी चरण सिंह के ग्रामीण वोट बैंक को अपनी-अपनी जातियों के आधार पर बांट लिया। कुर्मी नीतीश के साथ गये, पासवान दलित पासवान के साथ और अहीर अर्थात यादव लालू के साथ। ग्रामीण वोटों के इस बंटवारे से बिहार की राजनीति का कबायलीकरण जैसा हो गया। इन तीनों ही नेताओं ने अल्पसंख्यक समाज खासकर मुस्लिमों का समर्थन अपनी -अपनी ओर खींचने का भरसक प्रयास किया और इसमें उन्हें सफलता भी मिली, मगर बिहार विधानसभा के ताजा चुनाव अगले महीने होने जा रहे हैं। इन चुनावों में बिहार में एक नया प्रयोग रेवड़ियां को बांटने का हो रहा है। चुनाव से पूर्व सत्ता पक्ष की ओर से प्रदेश की 75 लाख गरीब महिलाओं के बैंक खाते में दस-दस हजार रुपये भेज दिये गये हैं। यह धन महिला आजीविका स्कीम के तहत स्थानान्तरित किया गया है। विपक्षी दल खासकर इंडिया गठबन्धन इसे मतदाताओं को दी गई रिश्वत के तौर पर बता रहा है, जबकि यह रकम एक सरकारी स्कीम के तहत दी गई है और कहा जा रहा है कि यह कुल दो लाख रुपए दी जाने वाली मदद की पहली किश्त है। विपक्ष जिस प्रकार इस मदद की आलोचना कर रहा है उससे उसकी निराशा का पता तो चलता है, मगर वह पूरी बहस को लोकतन्त्र में नागरिकों के अधिकार से जोड़ देना चाहता है।

यह बिल्कुल सही है कि लोकतन्त्र में नागरिकों को जो भी सुविधा मिलती है वह किसी की कृपा पर निर्भर नहीं होती बल्कि इसे संवैधानिक अधिकार के रूप में ही दिया जाता है। बेशक इसमें देर हो सकती है, किन्तु जो भी नागरिकों को मिलता है वह उनके कानूनी हक के तौर पर ही मिलता है, इसलिए लालू जी के पुत्र तेजस्वी यादव ने संभवतः बहुत दिमाग लड़ा कर नकद पैकेज मदद की काट खोजने का प्रयास किया है और घोषणा की है कि यदि इंडिया गठबन्धन चुनावों के बाद 14 नवम्बर को बिहार में सत्तारूढ़ होता है तो वह प्रत्येक परिवार से किसी एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी अवश्य देंगे और इसके लिए बाकायदा एक कानून बनायेंगे। बिहार में 2023 के सामाजिक सर्वेक्षण के अनुसार कुल दो करोड़ 76 लाख परिवार हैं जिनके 27.5 लाख लोग सरकारी नौकरियों में लगे हुए हैं।

पाक आतंकवाद और कांग्रेस

प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 26 नवम्बर 2008 के मुम्बई आतंकवादी हमले की याद दिलाकर पाकिस्तान की भारत के खिलाफ की गई कारस्तानियों की फेहरिस्त खोल दी है। अपने जन्म से लेकर आज तक पाकिस्तान का भारत के प्रति रुख दुश्मनी भरा ही रहा है जबकि भारत का नजरिया अपने सभी पड़ोसियों के प्रति प्रेम भाव का रहा है। वर्ष 2008 में तो पाकिस्तान ने सारी सीमाओं को लांघ दिया था और मुम्बई शहर में खुलेआम कत्लोगारत का बाजार गर्म कर दिया था, जिसमें 167 देशी-विदेशी नागरिक मारे गये थे। इस घटना से केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरा विश्व सकते में आ गया था क्योंकि जिन लोगों ने इस नृशंस हत्याकांड को अंजाम दिया था वे पाकिस्तान से ही जल मार्ग से कराची से मुम्बई पहुंचे थे। श्री मोदी का कहना है कि इस जघन्य कांड का विरोध तब भारत ने सैनिक जवाब देकर नहीं किया जबकि इसकी वक्ती जरूरत थी। बेशक पाकिस्तान की इस कार्रवाई के जवाब में भारत मुंहतोड़ सैनिक कार्रवाई वैसी ही कर सकता था जैसी कि श्री मोदी ने 2014 में सत्ता संभालने के बाद हुई पाक की आतंकवादी गतिविधियों के खिलाफ की और पाकिस्तान के घर में घुस कर उसे कई बार सबक सिखाया। 2008 नवम्बर महीने में जब पाकिस्तानी आतंकवादियों ने मुम्बई में यह जघन्य कांड किया तो इसके विदेश मन्त्री महमूद कुरैशी भारत की चार दिन की राजकीय यात्रा पर आये हुए थे। उनकी भारत की सरजमीं पर मौजूदगी के दौरान ही मुम्बई में यह घटना घटी थी। तब भारत के विदेश मन्त्री भारत रत्न स्व. प्रणव मुखर्जी थे। श्री मुखर्जी ने महमूद कुरैशी को बैरंग इस्लामाबाद वापस लौटा दिया था। कुरैशी ने तब कहा था कि इस काम में पाकिस्तान का सीधा हाथ नहीं है, बल्कि कुछ गैर सरकारी लोगों (नान स्टेट एक्टर) का यह काम है। भारत ने पाकिस्तान के इस कथन को स्वीकार करने से इन्कार कर दिया था और कहा था कि उसकी फौज के साये में पाकिस्तान में आतंकवादी फलफूल रहे हैं जो समय-समय पर भारत में आतंकवाद फैलाते रहते हैं और निरीह नागरिकों की जान लेते रहते हैं। सवाल यह है कि क्या उस समय 2008 में हुकूमत पर काबिज मनमोहन सरकार मुम्बई हमले का सैनिक कार्रवाई करके जवाब देना चाहती थी? तो इसका जवाब हमें 'हां' में मिलेगा परन्तु कांग्रेस पार्टी के भीतर ही कुछ तत्व ऐसे थे जो पाकिस्तान के खिलाफ सैनिक कार्रवाई नहीं चाहते थे। उस समय के अखबारों में इस तरह की खबरें भी छपी थीं कि तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. मनमोहन सिंह सैनिक कार्रवाई के प्रबल पक्षधर थे मगर उन्हें ऐसा करने से रोक दिया गया था और विदेश मन्त्री प्रणव मुखर्जी पर यह जिम्मेदारी डाल दी गई थी कि वह कूटनीतिक मोर्चे पर यह लड़ाई लड़ें। स्व. मुखर्जी ने तब इस मोर्चे पर ऐसा समां बांध दिया था कि पाकिस्तान के एक आतंकवादी देश घोषित होने की नौबत आ गई थी। इस्लामी दुनिया के देशों से लेकर राष्ट्रसंघ तक में पाकिस्तान अकेला पड़ गया था। तब श्री मुखर्जी ने अपने कनिष्ठ सहयोगी विदेश राज्य मन्त्री श्री ई. अहमद को राष्ट्रसंघ में भेजकर यह ऐलान कराया था कि पाकिस्तान में आतंकवादी संगठन अपना नाम बदल कर दहशतगर्दी में लगे रहना चाहते हैं।

डेड इकोनॉमी कहने वालों को करारा जवाब

भारत-ब्रिटेन नई आर्थिक साझेदारी की दास्तान - प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर की ऐतिहासिक सफ़ल भारत यात्रा 2025- व्यापार निवेश,तकनीक और विश्वास की नई परिभाषा

वैश्विक स्तरपर ब्रिटिश प्रधानमंत्री सर कीर स्टार्मर की 9-10 अक्टूबर 2025 की भारत यात्रा ने अंतरराष्ट्रीय राजनीति और वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक नया अध्याय जोड़ दिया है। यह यात्रा केवल दो दिनों की औपचारिक मुलाकात नहीं, बल्कि 21वीं सदी के वैश्विक व्यापारिक समीकरणों में भारत की निर्णायक भूमिका को स्वीकार करने की ठोस अभिव्यक्ति है।भारतीय पीएम के निमंत्रण पर भारत पहुंचे स्टार्मर का मुंबई एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत हुआ, जहां से इस यात्रा की शुरुआत ने एक ऐसा संदेश दिया भारत अब वैश्विक शक्ति संतुलन का निर्णायक केंद्र है।पीएम ने ब्रिटेन पीएम के साथ मुलाकात की एक तस्वीर साझा करते हुए कहा कि भारत और ब्रिटेन के रिश्ते तेजी से आगे बढ़ रहे हैं औरनई ऊर्जा से भरे हुए हैं।एक तस्वीर में पीएम मोदी ब्रिटिश पीएम के साथ एक ही कार में नजर आए मैं एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी गोंदिया महाराष्ट्र यह मानता हूं कि अमेरिका द्वारा भारत को डेड इकोनामी कहे जाने व 100 प्रतिशत तक टैरिफ लगाने के बाद भारत-यूके रिश्तों का नया दौर शुरू हो गया है,व्यापार, निवेश और प्रौद्योगिकी पर केंद्रित कूटनीति ने यह सिद्ध कर दिया है कि भारत डेड इकोनामी नहीं है,आज हम मीडिया में उपलब्ध जानकारी के सहयोग से आर्टिकल के माध्यम से चर्चा करेंगे, भारत-ब्रिटेन नई आर्थिक साझेदारी की दास्तान,प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर की ऐतिहासिक सफल भारत यात्रा 2025- व्यापार,निवेश, तकनीक और विश्वास की नई परिभाषा। साथियों बात अगर हम ब्रिटेन पीएम की दो दिवसीय यात्रा की करें तो,यह ऐसे समय में हो रही है जब भारत और ब्रिटेन दोनों ही अपने-अपने आर्थिक और रणनीतिक भविष्य के पुनर्संरचना के दौर से गुजर रहे हैं। यात्रा का प्रमुख उद्देश्य व्यापार, निवेश और प्रौद्योगिकी सहयोग को सुदृढ़ करना है। ब्रिटिश पीएम के साथ आए उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल में 125 से अधिक शीर्ष सीईओ,अग्रणी उद्यमी, विश्वविद्यालयों के कुलपति और सांस्कृतिक संस्थानों के प्रमुख शामिल हैं, यह अपने आप में इस यात्रा के महत्व को रेखांकित करता है।यह केवल एक राजनयिक यात्रा नहीं, बल्कि ब्रिटिश व्यापारिक समुदाय का भारत के प्रति बदलता नजरिया दर्शाने वाली ऐतिहासिक घटना है। ब्रिटेन के कई औद्योगिक घराने अब भारत को मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी हब के रूप में देख रहे हैं, न कि केवल एक उपभोक्ता बाजार के रूप में।डेड इकोनॉमी कहने वालों को करारा जवाब है। साथियों बात अगर हम अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा कुछ समय पहले भारत की अर्थव्यवस्था को डेड इकोनामी कहकर प्रश्न उठाए गए थे। वहीं भारत पर 100 प्रतिशत टैरिफ लगाने के बाद, वैश्विक व्यापार जगत में भारत की नीतियों को लेकर बहस तेज हो गई थी लेकिन ब्रिटिश प्रधानमंत्री की यह यात्रा उस सोच को सीधा जवाब देती है। ब्रिटिश पीएम ने मुंबई में उतरते ही कहा कि भारत 2028 तक दुनियाँ की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है, और ब्रिटेन उस यात्रा का मजबूत भागीदार बनेगा।यह बयान न केवल आर्थिक विश्वास का प्रतीक है, बल्कि यह उन तमाम संशयवादियों के लिए एक संदेश है जो भारत की विकास गाथा पर सवाल उठाते रहे हैं। साथियों बातें कर हम ब्रिटेन के जेम्बो डेलिगेशन की करें तो यह विश्वास की कूटनीतिक मिसाल है, इतिहास में शायद ही ऐसा हुआ हो जब ब्रिटेन का इतना बड़ा प्रतिनिधिमंडल किसी देश की यात्रा पर आया हो। यह जेम्बो डेलिगेशनभारत-ब्रिटेन संबंधों की गहराई और गंभीरता दोनों को दर्शाता है। 125 से अधिक शीर्ष सीईओ और शिक्षाविदों के साथ प्रधानमंत्री स्टार्मर का आना इस बात की पुष्टि करता है कि ब्रिटेन भारत को एक ऐसे रणनीतिक सहयोगी के रूप में देख रहा है, जो उसके पोस्ट-ब्रेक्सिट युग में वैश्विक प्रभाव को बनाए रख सकता है।इस प्रतिनिधिमंडल में ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जैसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों के कुलपति शामिल हैं, जो शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में भारत के साथ साझेदारी की नई संभावनाओं पर विचार करेंगे। वहीं, तकनीकी कंपनियों के प्रमुख भारत में एआई, ग्रीन एनर्जी,साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल इनोवेशन जैसे क्षेत्रों में निवेश की नई संभावनाओं को तलाश रहे हैं। साथियों बात अगर हम मोदी- स्टार्मर शिखर वार्ता साझेदारी की नई परिभाषा की करें तो नई दिल्ली में मोदी और कीर स्टार्मर के बीच हुई शिखर बैठक में व्यापार, प्रौद्योगिकी, सुरक्षा और संस्कृति को केंद्र में रखकर गहन चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने यह स्पष्ट किया कि भारत-यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को शीघ्र अंतिम रूप दिया जाएगा।बैठक में भारत ने ब्रिटेन को रक्षा उत्पादन, अंतरिक्ष तकनीक और ग्रीन एनर्जी मिशनों में साझेदारी के लिए आमंत्रित किया। वहीं ब्रिटेन ने भारत में अपने निवेश को तीन गुना बढ़ाने का आश्वासन दिया।इनोवेशन पार्टनरशिपके तहत दोनों देशों के बीच स्टार्टअप्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्रों में संयुक्त रिसर्च पर सहमति बनी। साथियों बात अगर हम भारत की ओर झुकता ब्रिटेन, वैश्विक शक्ति समीकरण में बदलाव कोसमझने की करें तो, ब्रिटेन पीएम की यात्रा ब्रिटिश विदेश नीति में एक मौलिक परिवर्तन का प्रतीक है। यह वही ब्रिटेन है जिसने दशकों तक भारत को डेवलपिंग नेशन की दृष्टि से देखा था। लेकिन अब यह मान्यता बदल चुकी है।

भारत को ब्रिटेन अब एक इक्वल पार्टनर, एक टेक्नोलॉजिकल पॉवरहाउस और एक वैश्विक निवेश गंतव्य के रूप में स्वीकार कर रहा है।ब्रेक्सिट के बाद ब्रिटेन को यूरोपीय संघ के बाहर नए आर्थिक साझेदारों की तलाश थी। ऐसे में भारत उसकी पहली प्राथमिकता बनकर उभरा है। ब्रिटिश मीडिया इसेब्रेकिंग पीवोट टू इंडिया कह रहा है। साथियों बात अगर हम भारत के लिए अवसर और जिम्मेदारी दोनों को समझने की करें तो,यह यात्रा भारत के लिए एक बड़ा अवसर लेकर आई है, लेकिन इसके साथ जिम्मेदारी भी जुड़ी है।

भारत को अब यह साबित करना होगा कि वह केवल निवेश आकर्षित करने वाला देश नहीं, बल्कि विनिर्माण, नवाचार और नीति स्थिरता के लिहाज से विश्वसनीय साझेदार भी है।भारत के लिए यह समय है कि वह अपने मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, और स्टार्टअप इंडिया जैसे कार्यक्रमों को ब्रिटिश सहयोग के साथ वैश्विक स्तर पर पहुंचाए। विशेष रूप से एआई, सेमीकंडक्टर, और क्लाइमेट टेक्नोलॉजी में भारत की भूमिका निर्णायक बन सकती है। साथियों बात अगर हम संस्कृति और शिक्षा,साझेदारी के मानवीय आयाम को समझने की करें तो,भारत-ब्रिटेन संबंध केवल अर्थव्यवस्था तक सीमित नहीं है। दोनों देशों के बीच संस्कृति, शिक्षा और सामाजिक मूल्य का भी गहरा जुड़ाव है। इस यात्रा में कल्चरल एक्सचेंज मिशन पर भी सहमति बनी, जिसके तहत ब्रिटेन और भारत के बीच कलाकारों, फिल्म निर्माताओं और विद्यार्थियों के आदान-प्रदान को बढ़ावा मिलेगा।ब्रिटिश विश्वविद्यालयों में भारतीय छात्रों की संख्या पहले ही रिकॉर्ड स्तर पर है। अब ब्रिटेन ने भारत को प्राथमिक शिक्षा भागीदार के रूप में मान्यता देने का निर्णय लिया है। इसके तहत उच्च शिक्षा में द्विपक्षीय डिग्री कार्यक्रम, स्कॉलरशिप्स और कोर्स एक्सचेंज की शुरुआत होगी। साथियों बात अगर हम यात्रा का ऐतिहासिक महत्व भविष्य के वैश्विक समीकरणों की झलक, यह यात्रा केवल भारत और ब्रिटेन के संबंधों की मजबूती का प्रतीक नहीं, बल्कि वैश्विक शक्ति समीकरणों में एशिया की केंद्रीय भूमिका को भी स्थापित करती है।जब दुनियाँ अमेरिका- चीन प्रतिस्पर्धा में उलझी हुई है, तब ब्रिटेन का भारत की ओर झुकाव इस बात का संकेत है कि 21वीं सदी का आर्थिक केंद्र अबएशिया की धरती पर स्थित है।भारत इस साझेदारी से न केवल व्यापारिक लाभ प्राप्त करेगा, बल्कि वह पश्चिमी देशों के साथ अपने कूटनीतिक संतुलन को भी और मजबूत करेगा।

अतः अगर हम उपरोक्त पूरे विवरण का अध्ययन कर इसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि विश्वास, साझेदारी और भविष्य की एक नई कहानी,ब्रिटिश पीएम की भारत यात्रा 2025 इतिहास में इकोनॉमिक डिप्लोमेसी के पुनर्जागरण के रूप में दर्ज होगी। इस यात्रा ने दिखा दिया कि भारत अब किसी के समर्थन का आकांक्षी नहीं, बल्कि साझेदारी का निर्णायक केंद्र बन चुका है।ब्रिटेन के लिए यह यात्रा भारत के प्रति विश्वास की पुनर्स्थापना है, वहीं भारत के लिए यह अपनी वैश्विक स्थिति को और ऊंचा उठाने का अवसर। व्यापार, शिक्षा, तकनीक और संस्कृति,इन चारों स्तंभों पर खड़ी यह नई साझेदारी आने वाले दशक में विश्व की आर्थिक दिशा तय कर सकती है।भारत और ब्रिटेन अब केवल साझेदार नहीं, बल्कि वैश्विक पुनरुत्थान के सह-निर्माता हैं, एक ऐसा अध्याय जो आने वाली पीढ़ियाँ न्यू ऐज ऑफ़ इंडो - ब्रिटिश पार्टनरशिप के नाम से याद करेंगी।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक विजय कुमार घाटी ने वन्दना ऑफसेट प्रिन्टर्स, ए-9, साय पैंचशील एक्स. दिल्ली-33, से मुद्रित कर कार्यालय, बी-2/370, सुल्तानपुरी, दिल्ली-86 से प्रकाशित किया सम्पादक : विजय कुमार घाटी, मो. : 09582093548 समाचार पत्र में प्रकाशित सामग्री से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं विवादास्पद केवल दिल्ली कोर्ट में होंगे। (DELHIN/2011/0882)

प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के शुभारंभ पर उत्कृष्ट कार्य करने वालों को मिला सम्मान

देवरिया।

रोटरी सभागार में शनिवार को प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के शुभारंभ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में शासन से प्राप्त दिशा-निर्देशों के तहत राष्ट्रीय गोकुल मिशन अंतर्गत अन्य योजनाओं की लाइव स्क्रीनिंग भी की गई।

इस अवसर पर जिलेभर में पशुपालन, कृषि एवं ग्रामीण विकास के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली 31 मैत्रियों को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथियों के रूप में जिला विकास अधिकारी, मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी, उप मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी, नोडल अधिकारी (गोकुल मिशन), उप कृषि निदेशक, जिला कृषि अधिकारी, जिला मत्स्य अधिकारी, भाजपा जिला उपाध्यक्ष गंगा सिंह कुशवाहा एवं भाजपा किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष पवन मिश्रा सहित कई अधिकारी एवं कर्मी उपस्थित रहे। सम्मानित मैत्रियों में कृपासागर धर द्विवेदी, उमेश कुमार यादव, अभिषेक कुमार, दीपक कुमार, सचिन कुमार, अमित कुमार गुप्ता, मलबाबू यादव, शशिभूषण सिंह, अमित गौर, रामकिशुन प्रसाद, मुहम्मद यासिन,

31 मैत्रियाँ व 1962 एम्बुलेंस टीम सम्मानित

अश्वनी कुमार, राजन कुमार, विनोद कुमार शर्मा, कन्हैया लाल पासवान, आकाश कन्नौजिया, धर्मेंद्र कुशवाहा, सत्यम कुमार पांडेय, आशुतोष प्रताप सिंह, आदित्य नारायण तिवारी, संदीप कुमार, श्रीप्रकाश मौर्य, रामदास, दुर्गेश कुमार, रंजन विजय गौतम, सुनील प्रजापति, रामशंकर यादव, जय सिंह, बाबूलाल प्रसाद, ज्ञानेश्वर गौड़ एवं रीता देवी शामिल रहीं। इसके अतिरिक्त 1962 एम्बुलेंस टीम के उत्कृष्ट कार्य को भी सराहा गया। टीम के सदस्य डॉ. अंकित यादव (पशुचिकित्सक), विनोद कुमार (एम.टी.एस.) एवं राम (वाहन चालक) को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना किसानों एवं पशुपालकों के जीवन में आर्थिक मजबूती और आत्मनिर्भरता लाने का माध्यम बनेगी। इस योजना से न केवल कृषि उत्पादन बढ़ेगा बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में भी नई ऊर्जा का संचार होगा।

मानसिक स्वास्थ्य के लिये ऐसे शिविर निरन्तर लगे-सांसद

पड़रौना,कुशीनगर। स्वशासी मेडिकल कालेज के परिसर में शनिवार को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर विशाल मानसिक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन जिला सँयुक्त चिकित्सालय द्वारा किया गया। विशाल मानसिक स्वास्थ्य शिविर का शुभारंभ मुख्य अतिथि सांसद विजय कुमार दुबे द्वारा फीता काटकर किया गया। ततपश्चात सीडीओ गुंजन द्विवेदी के साथ शिविर में लगे स्टालों का निरीक्षण भी किया। कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुये सांसद ने कहा कि भौतिकवादी युग की भागदौड़ में ज्यादातर लोग मानसिक तनाव से गुजर रहे है और उनके स्वयं पर ध्यान न देने से यह अवसाद का रूप ले रहा है। जिसके कारण वह व्यक्ति तथा उसका परिवार प्रभावित हो रहा है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग द्वारा उस व्यक्ति की नियमित रुप से कॉउंसिल के साथ उसे उपचारित कर उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने में अपनी महती भूमिका निभा रहा है। मैं जनपद में कार्यरत मानसिक स्वास्थ्य की पूरी टीम को साधुवाद देता हूँ। उन्होंने कहा कि ऐसे शिविरों का आयोजन एक विशेष दिवस पर न होकर बल्कि नियमित अंतराल पर पूरे जनपद में लगाया जाये जिससे मानसिक रूप से पीड़ित व्यक्ति इसका लाभ उठाकर

-थीम सेवाओं तक पहुँच- आपदाओं और आपात स्थितियो में मानसिक स्वास्थ्य
-विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस पर आयोजित हुआ विशाल मानसिक स्वास्थ्य शिविर
-शिविर में 452 मरीजों का पंजीकरण कर उनका उपचार किया गया।

वह स्वस्थ हो सके। कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुये सीएमओ डॉ चंद्रप्रकाश ने कहा कि जनपद में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम टीम द्वारा जनपद के 52 इंटर कॉलेजों में लगभग 35000 बच्चों को मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक कर परीक्षा के समय होने वाले तनाव से बचने के उपाय बताये गये। इनके द्वारा 480 बच्चों की काउंसलिंग प्रदान की गयी। विभिन्न कार्यस्थलों पर लगभग 350 कर्मचारियों को तनाव प्रबंधन के विभिन्न तकनीकों की जानकारी दी गयी। उन्होंने ने कहा कि हम जनपद के सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर मानसिक शिविर लगाकर ऐसे मरीजों को लाभान्वित करते है।शिविर में कुल 452 मरीजों का पंजीकरण कर उनका उपचार किया गया। कार्यक्रम को क्लीनिकल साइकोलिस्ट अमृता कुमारी एवं मनोरोग सामाजिक कार्यकत्री योगिता कुशवाहा ने भी सम्बोधित किया। कार्यक्रम में मानसिक रूप से विकलांग दो बच्चों को विकलांगता प्रमाण पत्र दिया गया। उत्कृष्ट कार्य करने वाले चिकित्सक एवं कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया जिसमें मानसिक रोग चिकित्सक बृज किशोर,अमित आदि प्रमुख रहे।

स्काउट गाइड शिविर का हुआ समापन

पडरौना,कुशीनगर। जनपद में स्काउटिंग गाइडिंग कार्यक्रम के अंतर्गत परिषदीय विद्यालयों में जिला मुख्य आयुक्त एवम मुख्य विकास अधिकारी गुंजन दिवेदी और जिला आयुक्त एवम जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉक्टर राम जियावन मौर्य के निर्देशन में पी एम श्री विद्यालय दुर्गवलिया में स्काउट गाइड शिविर का आयोजन दिनांक 9 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक किया गया। इस शिविर में स्काउट की 04 टोलियो तथा गाइड की 6 टोलियो ने प्रतिभाग किया। प्रत्येक टोली में 8-8 की संख्या रही। प्रत्येक टोली में एक दल नायक और दल नायिका बनाकर उनमें नेतृत्व की भावना का विकास किया गया। शिविर में मार्च पास्ट, कलर पार्टी, प्राथमिक सहायता, टेंट निर्माण, गांठ बंधन, अस्थाई पुल बनाना, कमांडो ब्रिज, मंकी ब्रिज और विषम परिस्थितियों में जीवन जीने की कला का प्रशिक्षण दिया गया। शिविर में सभी टोलियो ने अपने टेंट का निर्माण किया और बिना बर्तन के भोजन बनाने की कला का प्रदर्शन किया। शिविर समापन के अवसर पर मुख्य अतिथि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉक्टर राम जियावन मौर्य ने सभी टेंट का निरीक्षण किया और उनकी सराहना की। अपने संबोधन में मुख्य अतिथि ने कहा कि स्काउटिंग गाइडिंग से जीवन में अनुशासन और देश प्रेम के साथ साथ समाज की सेवा का भाव भी विकसित होता है जो देश के विकास में सहायक होता है। इस प्रकार के आयोजन से बच्चो में शारीरिक और मानसिक क्षमता का विकास होता है तथा समूह में कार्य करने का ज्ञान प्राप्त होता है। इस अवसर पर जिला स्काउट मास्टर नीरज बंका, एआरपी अखिलेश सिंह, प्रधानाध्यापक सुधीर कुमार श्रीवास्तव, दीपक कुमार, रामायण यादव, प्रिंस त्रिपाठी, सुबोध शुक्ल, विद्यावती सिंह, योगेंद्र, तथा स्काउट काउंसलर रईस, राहुल, पंकज सहित समस्त रसोइया उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन शिव शंकर तिवारी ने किया।

रेडियो प्रज्ञा ने पूरे किए सफलता के 8 वर्ष

कुशीनगर।

कारवाँ सांस्कृतिक एवं विकास मंच के तत्वाधान में संचालित स्थानीय सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो प्रज्ञा 90.4 एफएम ने सफलता के 8 वर्ष पूरे किए। 11 अक्टूबर 2017 से संचालित रेडियो प्रज्ञा नें जनपद कुशीनगर में श्रोताओं के लिए मनोरंजन के साथ-साथ एक महत्वपूर्ण सूचना का माध्यम बनकर जो प्रतिष्ठा अर्जित की है वह अत्यंत प्रशंसनीय है। इसी कारण जनपद के माननीय सांसद, माननीय विधायक गणों,सुप्रसिद्ध चिकित्सकों, प्रतिष्ठित व्यवसाईयों, शिक्षाविदों एवं समाजसेवियों के द्वारा रेडियो प्रज्ञा को अपने स्थापना दिवस पर बड़ी संख्या में बधाई संदेश प्राप्त हुए। रेडियो प्रज्ञा को अपने बधाई संदेश में सांसद कुशीनगर विजय कुमार दुबे ने कहा की इन 8 वर्षों में रेडियो प्रज्ञा ने जनपद में सूचना के स्तर पर जो आम

माननीय सांसद, माननीय विधायक गण, आदरणीय चिकित्सकगण प्रतिष्ठित व्यवसायियों, शिक्षाविदों एवं समाज सेवियों ने प्रेषित की अपनी शुभकामनाएं

जनमानस में अपनी जो प्रतिष्ठा बनाई है

हम यह उम्मीद करते हैं कि यह अनवरत आगे जारी रहेगा। सदर विधायक मनीष जायसवाल उर्फ मंटू भैया,कुशीनगर विधायक पी एन पाठक, विधायक खड्डा विवेकानंद पांडे, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष दुर्गेश राय, वरिष्ठ भाजपा नेता एन पी कुशवाहा,नगर पालिका पडरौना के अध्यक्ष विनय जायसवाल, विकासखंड विशुनपुरा के ब्लॉक प्रमुख विंध्यवासिनी श्रीवास्तव गौतम, समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष और पूर्व विधान परिषद सदस्य राम अवध यादव,पडरौना विधानसभा क्षेत्र के पूर्व प्रत्याशी राजेंद्र उर्फ मुन्ना यादव, ने रेडियो प्रज्ञा के कार्यक्रमों की सराहना करते हुए उसके उज्जवल भविष्य की है। जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर बृज किशोर, बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉक्टर राम जियावन, मौर्य,जिला प्रतिरक्षण अधिकारी डॉक्टर मुकेश यादव, प्रतिष्ठित चिकित्सागण में प्रमुख रूप से चिकित्सक डॉक्टर संदीप अरुण श्रीवास्तव, डॉक्टर कमलेश वर्मा, देवशरण सिंह, डॉ मनोज सिंह, डॉ वैभव ज्योति श्रीवास्तव डॉ रवि जयसवाल, डॉक्टर रुचिका सिंह, डॉक्टर प्रवीण राव, डॉ मनोज सिंह, प्रतिष्ठित व्यवसायी गण में प्रमुख रूप से दीप नारायण अग्रवाल, दिनेश पांडे, रवि अग्रवाल, राजेश जायसवाल राजू भैया, संजीव कुमार गुप्ता, अंशुल जायसवाल, प्रबंध निदेशक सेंट जेवियर डॉक्टर अरुण श्रीवास्तव प्रबंधक हनुमान इंटरमीडिएट कॉलेज मनोज शर्मा सारस्वत, प्रधानाचार्य शैलेंद्र दत्त शुक्ला, मारवाड़ी युवा मंच चेतना महिला शाखा की अध्यक्ष श्रीमती मीनू जिंदल, डॉ सुरभि श्रीवास्तव, श्रीमती दीपाली श्रीवास्तव, योगिता कुशवाहा, अंशुल जायसवाल, आदि के द्वारा रेडियो प्रज्ञा के सफलतम 8 वर्ष पूर्ण करने के अवसर पर अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए उज्जवल भविष्य की कामना की गई है। रेडियो प्रज्ञा के कार्यालय पर प्रबंध निदेशक परशुराम श्रीवास्तव,प्रबंधक तेज नारायण श्रीवास्तव,कार्यक्रम नियंत्रक आर के भट्ट,सीनियर आरजे कुंवर रैना, आर जे मोनिका, आर जे सोनिया, सुमित श्रीवास्तव,तेज सिंह, आदि की उपस्थिति में केक काटकर स्थापना दिवस को सेलिब्रेट किया गया। रेडियो प्रज्ञा की रेडियो जॉकी की टीम के द्वारा फेसबुक लाइव कर अपने श्रोताओं एवं दर्शकों से सीधा संवाद भी किया गया।

प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के अंतर्गत कृषकों को प्रमाण पत्र एवं कृषि यंत्र वितरित

कुशीनगर। भारत सरकार द्वारा नई दिल्ली से प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। कार्यक्रम के क्रम में राष्ट्रीय गोकुल मिशन अंतर्गत मैत्री प्रमाण पत्र वितरण एवं अन्य कार्यक्रमों के साथ-साथ जनपद कुशीनगर में कृषि विभाग की ओर से भी कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सांसद विजय कुमार दूबे रहे, जिन्होंने पशुपालन विभाग के अंतर्गत जनपद के 23 उत्कृष्ट मैत्रियों को प्रमाण पत्र तथा 09 नई मैत्रियों को कृत्रिम गर्भाधान यंत्र वितरित किए। इस अवसर पर कृषि विभाग की ओर से लल्लन सिंह, बकरखुर्द फार्मर को मिशन ऑन एग्रीकल्चर मेकनाइजेशन योजना के तहत चारा काटने की मशीन वितरित

की गई।

प्रधानमंत्री धन धान्य योजना के अंतर्गत दलहन फसलों के प्रोत्साहन के लिए जनपद के विभिन्न राजकीय बीज भंडारों पर चना, मटर एवं मसूर के बीज का सामान्य वितरण के साथ-साथ निःशुल्क मिनी किट का वितरण भी किया जा रहा है। जो किसान मिनी किट प्राप्त करना चाहते हैं, वे राजकीय भंडारों पर बुकिंग कर सकते है। इस संबंध में आवश्यक जानकारी जिला कृषि अधिकारी कुशीनगर द्वारा प्रदान की गई है। कार्यक्रम में सांसद विजय कुमार दूबे के साथ मुख्य विकास अधिकारी गुंजन द्विवेदी, मुख्य पशुचिकित्साधिकारी रवींद्र प्रसाद, उप कृषि निदेशक अतिंद्र सिंह एवं जिला कृषि अधिकारी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

बीजेपी की वोट चोरी पर लगाम लगी तो दिल्ली निगम उपचुनाव में जीतेगी कांग्रेस, देवेंद्र यादव का बड़ा दावा

नई दिल्ली । दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेन्द यादव ने आज प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में 12 वार्डों के निगम उपचुनावों को लेकर एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की. बैठक में 5 सदस्यीय कोऑर्डिनेशन कमेटी, 12 ऑब्जर्वर और संबंधित वार्डों के जिला अध्यक्ष मौजूद रहे. इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष देवेन्द यादव के अलावा दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री डॉ. नरेंद नाथ, पूर्व विधायक हरी शंकर गुप्ता, सुरेंद कुमार, राजेश गर्ग, जिला अध्यक्ष सिद्धार्थ राव, राजेश चौहान, जावेद मिर्जा, सतबीर शर्मा, दिनेश कुमार, विरेन्द कसाना, मुदित अग्रवाल, रागिनी नायक, निगम पार्षद हाजी जरीफ, प्रदेश महिला अध्यक्ष पुष्पा सिंह, नीतू वर्मा और विनीत यादव शामिल रहे. इस दौरान देवेन्द यादव ने स्पष्ट किया कि, अगर दिल्ली राय चुनाव आयोग निगम उपचुनाव जल्दी कराता है, तो कांग्रेस पार्टी पूरी तरह तैयार है. उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी की वोट चोरी पर लगाम लगाई गई तो कांग्रेस सभी 12 वार्डों में जीत हासिल करेगी. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि वो अपने नेता राहुल गांधी के संघर्ष से प्रेरित होकर भाजपा की संवैधानिक अधिकारों की चोरी के खिलाफ एकजुट होकर लड़ रहे है. दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने पिछले आठ महीनों में लोगों से किए एक भी वादे को पूरा नहीं किया है. आम आदमी पार्टी दिल्ली की राजनीति से लगभग विलुप्त होती जा रही है और जनता अब कांग्रेस को एक विकल्प के रूप में देख रही है. देवेन्द यादव ने निगम में भाजपा सरकार के प्रदर्शन पर सवाल उठाते हुए कहा कि दिल्ली में सफाई व्यवस्था चरमरा चुकी है. उन्होंने कहा कि भाजपा ने कूड़े के पहाड़ कम करने का दावा किया था लेकिन, आज भी सड़कों, गलियों और कॉलोनियों में गंदगी के ढेर और जलभराव आम बात बन चुकी है. भाजपा ने दिल्ली सरकार और निगम दोनों पर कब्जा कर लिया, लेकिन जनता के जीवन में कोई सुधार नहीं आया. दिल्लीवासी अब झूठे वादों और खोखले दावों का जवाब उपचुनाव में देंगे. देवेन्द यादव ने बताया कि अप्रैल माह में ही 12 निगम वार्डों के लिए ऑब्जर्वर और 5 सदस्यीय कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन किया जा चुका था. उन्होंने कहा कि सभी ऑब्जर्वर अपने-अपने वार्डों में सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर मतदाताओं की नब्ज टटोलने का काम कर रहे है. लोगों में बीजेपी की वोट चोरी के खिलाफ भारी रोष है. दिल्ली कांग्रेस ने 'संगठन सृजन अभियान' के तहत राजधानी में संगठन को जमीनी स्तर तक मजबूत किया है. उन्होंने बताया कि 14 जिला अध्यक्ष, 258 ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष, 520 मंडलम और प्रत्येक मंडलम के अंतर्गत सेक्टर इंचार्जों की नियुक्ति पूरी की जा चुकी है. कांग्रेस कार्यकर्ता हर गली-मोहल्ले में जाकर भाजपा की षड्यंत्रकारी वोट चोरी के खिलाफ लोगों को जागरूक कर रहे है और हस्ताक्षर अभियान में उनकी भागीदारी सुनिश्चित कर रहे है. कांग्रेस नेता ने कहा कि पार्टी ने प्रत्येक निगम वार्ड में मजबूत उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया पूरी कर ली है और अब पार्टी जीत के लक्ष्य को लेकर मैदान में उतर चुकी है. उन्होंने कहा, भले ही विधानसभा चुनाव में भाजपा जीती हो लेकिन, लोग अब कांग्रेस की चर्चा कर रहे है. अगर कार्यकर्ता मजबूती से अपना पक्ष रखें, तो उपचुनावों में कांग्रेस की जीत तय है.

पीएम मोदी का किसानों को दिवाली तोहफा, कृषि क्षेत्र के लिए 35,440 करोड़ की दो बड़ी योजनाएं की लॉन्च

नई दिल्ली ।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को देश के किसानों को बड़ी सौगात दी। प्रधानमंत्री ने कृषि क्षेत्र के लिए करीब 35,440 करोड़ रुपये की दो अहम योजनाओं की शुरुआत की।

इसमें करीब 24 हजार करोड़ रुपये की धन धान्य कृषि योजना की भी शुरुआत की गई। पीएम मोदी ने नई दिल्ली स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में विशेष कृषि योजना में शिरकत की।

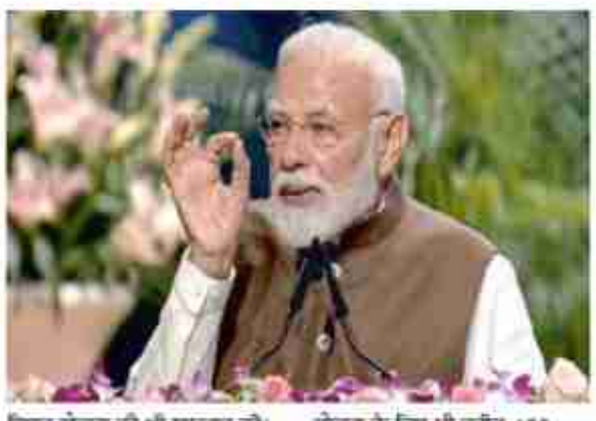

कार्यक्रम में पीएम मोदी ने लोकनायक जयप्रकाश की जयंती के अवसर पर जेपी को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के तहत सरकार देश के 100 जिलों में कृषि उत्पादन को बढ़ाने, किसानों को कर्ज देने, सिंचाई और फसलों में विविधता और फसल प्रबंधन को बेहतर करने का लक्ष्य तय किया गया है। साथ ही पीएम मोदी ने दालों में मामले में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए दाल उत्पादन मिशन योजना की भी शुरुआत की। यह योजना 11,440 करोड़ रुपये की है। करीब 3,650 करोड़ रुपये की लागत से कृषि आधारभूत ढांचा फंड योजना की शुरुआत की गई है। पशुपालन के लिए 17 विभिन्न प्रोजेक्ट्स के लिए करीब 1166 करोड़ रुपये भी जारी किए गए हैं।

मतस्य पालन योजना और फूड प्रोसेसिंग उद्योग पर भी फोकस

पीएम मोदी ने मतस्य पालन योजना के लिए भी करीब 693 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। फूड प्रोसेसिंग उद्योग को बढ़ावा देने के लिए करीब 800 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। सरकार किसानों के बीच प्राकृतिक खेती को लोकप्रिय करने के लिए भी योजना चला रही है। विशेष कृषि कार्यक्रम में हिस्सा लेने से पहले पीएम मोदी ने विभिन्न किसानों से मुलाकात की और उनसे कृषि क्षेत्र की चुनौतियों और इस क्षेत्र में हो रहे सकारात्मक बदलावों पर चर्चा की।

पिछली सरकारों ने खेती को उसके हाल पर छोड़ा- पीएम मोदी

पिछली सरकारों ने किसानों को उनके हाल पर छोड़ दिया

कृषि योजनाओं के लॉन्च के बाद अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा, आज 11 अक्टूबर का दिन बहुत ऐतिहासिक है। आज भारत माता के दो महान रत्नों की जयंती है जिन्होंने इतिहास रचा। भारत रत्न जयप्रकाश नारायण और भारत रत्न नानाजी देशमुख, ये दोनों महान सपूत ग्रामीण भारत की आवाज थे, लोकतांत्रिक क्रांति के अग्रदूत थे। वे किसानों और गरीबों के कल्याण के लिए समर्पित थे। आज इस ऐतिहासिक दिन पर देश की आत्मनिर्भरता और किसानों के कल्याण के लिए दो महत्वपूर्ण नई योजनाओं का शुभारंभ किया जा रहा है। उन्होंने कहा खेती और किसानी हमेशा से हमारी विकास यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहे हैं। यह जरूरी है कि सरकार बदलते समय के साथ कृषि और खेती को समर्थन देती रहे। दुर्भाग्य से, पिछली सरकारों ने कृषि को अपने हाल पर छोड़ दिया। सरकार के पास कृषि के लिए कोई दूरदर्शिता या दृष्टिकोण का अभाव था, जिसके कारण भारत की कृषि प्रणाली लगातार कमजोर होती गई।

हमने कृषि के प्रति पिछली सरकारों के लापरवाह रवैये को बदल दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि आज दलहन आत्मनिर्भरता मिशन का भी शुभारंभ हुआ है। यह केवल दलहन उत्पादन बढ़ाने का मिशन नहीं है, बल्कि हमारी भावी पीढ़ियों को सशक्त बनाने का भी मिशन है। हाल के वर्षों में, भारतीय किसानों ने रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन हासिल किया है। आज देश बड़ी मात्रा में दालों का आयात करता है, इसलिए दलहन आत्मनिर्भरता मिशन आवश्यक है।

महिला पत्रकारों से भेदभाव पर चुप्पी से नारी शक्ति पर प्रधानमंत्री के खोखले नारे उजागर हुए : राहुल गांधी

नई दिल्ली ।

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी के संवाददाता सम्मेलन में महिला पत्रकारों को शामिल होने की अनुमति नहीं दिए जाने से नारी शक्ति पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नारों का ''खोखलापन बेनकाब हुआ है। गांधी ने यह दावा भी किया कि प्रधानमंत्री ने साबित कर दिया कि वह ''इतने कमजोर है कि महिलाओं के लिए खड़े नहीं हो सकते। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री इन दिनों भारत के दौरे पर है। उन्होंने शुक्रवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ द्विपक्षीय वार्ता की थी। बाद में उन्होंने अलग से एक संवाददाता सम्मेलन को भी संबोधित किया था, जिसमें महिला पत्रकारों को शामिल होने की अनुमति कथित तौर पर नहीं थी। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा, मोदी जी, जब आप महिला पत्रकारों को एक सार्वजनिक मंच से बाहर किए जाने की अनुमति देते हैं, तो आप भारत की हर महिला को बता रहे हैं कि आप इतने कमजोर हैं कि उनके लिए खड़े नहीं हो सकते। उन्होंने कहा, हमारे देश में महिलाओं को हर क्षेत्र में समान भागीदारी का अधिकार है। ऐसे भेदभाव के सामने आपकी चुप्पी नारी शक्ति पर आपके नारों के खोखलेपन को उजागर करती है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाद्रा ने भी एक्स पर 'पोस्ट किया, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी, कृपया भारत दौरे पर तालिबान के प्रतिनिधि के संवाददाता सम्मेलन से महिला पत्रकारों को दूर रखे जाने पर अपना रुख स्पष्ट करें। उन्होंने कहा, यदि महिलाओं के अधिकारों के बारे में आपकी मान्यता सिर्फ एक चुनाव से दूसरे चुनाव में सुविधाजनक दिखावा नहीं है, तो हमारे देश में भारत की कुछ सबसे सक्षम महिलाओं के अपमान की अनुमति कैसे दी गई है, एक ऐसा देश जिसकी महिलाएं इसकी रीढ़ है और इसका गौरव है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि (तालि)बैन में महिला पत्रकारों पर प्रतिबंध लगाया गया और यह चौंकाने वाला और अस्वीकार्य है कि भारत सरकार इस पर सहमत हुई। उन्होंने कहा कि यह सब अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस की पूर्व संध्या पर दिल्ली में किया गया।

बड़ा खुलासा: एमपी में जहरीला कफ सिरप पीने से 150 से ज्यादा बच्चों की मौत, कांग्रेस का सनसनीखेज दावा

भोपाल। मध्य प्रदेश में बच्चों की रहस्यमयी मौतों को लेकर हालात लगातार गंभीर होते जा रहे हैं। जहरीले कफ सिरप से जुड़ा यह मामला अब राजनीतिक रंग भी लेने लगा है। राज्य के कई जिलों में बच्चों की असामान्य मौतों ने जहां परिजनों के आंसू नहीं थमने दिए हैं, वहीं स्वास्थ्य व्यवस्था पर भी बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। इस मुद्दे को लेकर एमपी कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक बेहद चौंकाने वाला दावा किया है। उन्होंने कहा कि सिर्फ छिंदवाड़ा और उससे लगे आदिवासी इलाकों में पिछले तीन महीनों में 150 से ज्यादा बच्चों की मौत हो चुकी है। इसके साथ ही करीब 500 से ज्यादा बच्चे गंभीर रूप से बीमार बताए जा रहे हैं। पटवारी ने इन मौतों के पीछे नकली या जहरीली दवाओं के इस्तेमाल की आशंका जताई है और इसे सरकारी लापरवाही का भयावह उदाहरण बताया। उन्होंने प्रदेश सरकार को सीधे कटघरे में खड़ा करते हुए मांग की कि पूरे प्रकरण की एसआईटी से जांच कराई जाए। जीतू पटवारी ने कहा कि जिन इलाकों में ये मौतें हुई हैं, वहां की स्वास्थ्य व्यवस्था पहले से ही चरमराई हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की ओर से न तो समय पर इलाज उपलब्ध कराया गया और न ही जहरीले कफ सिरप की सप्लाई की रोकथाम के लिए कोई कदम उठाया गया। उन्होंने यह भी पूछा कि जब बच्चों की मौत की खबरें लगातार सामने आ रही थीं, तब प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने क्या एक्शन प्लान तैयार किया? उन्होंने इस पूरे मामले को स्वास्थ्य महकमे की आपराधिक लापरवाही करार दिया।

एसआईटी जांच की मांग क्यों?

कांग्रेस अध्यक्ष का कहना है कि मौतों की वजहों को छिपाया जा रहा है। मौत के सही आंकड़े सामने नहीं आ रहे है और सरकारी तंत्र लीपापोती में लगा हुआ है।

पटवारी ने स्पष्ट कहा कि अगर सरकार को सच से डर नहीं है, तो तुरंत एसआईटी का गठन करे और दूध का दूध, पानी का पानी करे।

उत्तर प्रदेश में पराली जलाने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई, सीएम योगी ने जारी किए कड़े निर्देश

लखनऊ।

उत्तर प्रदेश में पराली जलाने की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर सख्त रुख अपनाया है। मुख्यमंत्री ने सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में पराली जलाने की घटनाओं को 'शून्य' किया जाए। इस संबंध में शासनादेश के तहत विस्तृत दिशा-निर्देश पहले ही जारी किए जा चुके है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पराली जलाने से पर्यावरण प्रदूषण बढ़ता है और जनस्वास्थ्य पर भी गंभीर प्रभाव पड़ता है। इसलिए किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन के वैकल्पिक उपायों के प्रति जागरूक किया जाए। सभी जिलाधिकारियों से अपेक्षा की गई है वो सेटेलाइट के माध्यम से पराली जलाने की घटनाओं की लगातार निगरानी करें और संवेदनशील जिलों में विशेष सतर्कता बरती जाए। जारी निर्देशों के अनुसार, फसल अवशेष जलाने पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति लगाई जाएगी। दो एकड़ से कम क्षेत्र पर 2,500, दो से पांच एकड़ तक 5,000 और पांच एकड़ से अधिक पर 15,000 का जुर्माना निर्धारित किया गया है। प्रत्येक 50 से 100 किसानों पर एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी जो पराली जलाने की घटनाओं की रोकथाम सुनिश्चित करेंगे। मुख्यमंत्री ने जनप्रतिनिधियों से भी इस अभियान में सहयोग की अपील करते हुए कहा कि संयुक्त प्रयासों से ही स्वच्छ पर्यावरण और प्रदूषण मुक्त प्रदेश का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। निर्देशों के अनुसार, जिलाधिकारियों से कहा गया है कि हॉटस्पाट चिन्हित करते हुए 50/100 किसानों पर एक नोडल अधिकारीकी नियुक्ति किया जाए। नोडल अधिकारी को पराली जलाने की घटनाओं को शून्य करने के लिए विशेष हिदायत दी जाए। इसके साथ ही, राजस्व, पुलिस, कृषि, ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज विभागों के जनपद, तहसील, विकासखण्ड एवं क्षेत्रीय कर्मियों के माध्यमसे फसल कटने के समय निगरानी करते हुए, फसल अवशेष जलाने की घटनाओं को शून्य करना है। यदि कोई कृषक फसल अवशेष जलाता हुआ पाया जाता है तो मौके पर उसको रोकना तथा उस पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि अधिरोपित करते हुए कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाए।

विधायक मिश्रीलाल यादव ने किया भाजपा छोड़ने का एलान, बोले- पार्टी में मुझे प्रताड़ित किया गया

पटना । जनता दल यूनाइटेड के बाद भारतीय जनता पार्टी को बड़ा राजनीतिक झटका लगा है। दरभंगा जिले की अलीनगर विधानसभा सीट से भाजपा विधायक मिश्रीलाल यादव ने पार्टी से इस्तीफा देने का एलान कर दिया है। उन्होंने पार्टी नेतृत्व पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा अब पिछड़ों का सम्मान नहीं करती। पार्टी का शीर्ष नेतृत्व घमंड में चूर हो गया है। इस बात जनता इन्हें सबक सिखाकर रहेगी। मिश्रीलाल यादव ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि अलीनगर में पिछले 30 वर्षों से एनडीए का विधायक नहीं रहा। लेकिन, 2020 में मैंने वहां भाजपा का परचम लहराया। इसके बावजूद पार्टी ने मेरा अपमान किया है। भाजपा में मेरे स्वाभिमान की कोई कद्र नहीं है। मुझे लगातार प्रताड़ित किया गया। अब ऐसे दल में रहना मेरे जैसे स्वाभिमानी व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि वे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को अपना इस्तीफा पत्र सौंपने जा रहे हैं। मिश्रीलाल यादव ने साफ कर दिया कि वह अलीनगर से चुनाव जरूर लड़ेंगे, चाहे किसी भी दल से लड़ना पड़े। हालांकि उन्होंने अभी तक यह नहीं बताया कि वे किस पार्टी में शामिल होंगे। कहा कि मैं एक सेकुलर सोच रखने वाला व्यक्ति हूं, इसलिए संभव है कि मैं किसी सेकुलर पार्टी में जाऊं। लेकिन फिलहाल यह तय नहीं है कि किस पार्टी से जुड़ूंगा। उन्होंने कहा कि एक बात तय है कि मैं चुनाव लड़ूंगा और जीतूंगा भी।

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को पुलिस ने रोका, रायबरेली हरिओम के परिजनों से मिलने जा रहे थे

लखनऊ । लखनऊ में कांग्रेस कार्यालय के बाहर भारी पुलिस फोर्स तैनात है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय रायबरेली में हरिओम वाल्मीकि के परिजनों को आर्थिक मदद देने के लिए जाने की तैयारी में है।

लेकिन, पुलिस ने उनको रास्ते में ही रोक लिया है। इसी वजह से पार्टी कार्यालय पर सुबह से ही भारी संख्या में फोर्स लगा दी गई है। पुलिस का कहना है कि किसी भी हालत में रायबरेली नहीं जाने दिया जाएगा। दरअसल, हरिओम वाल्मीकि की मॉब लिंचिंग के दौरान मौत हो गई थी। जिस वक्त लोग पीट रहे थे, उसे समय हरिओम ने राहुल गांधी का नाम लेते हुए गुहार लगाई थी। राहुल गांधी ने भी फोन करके हरिओम के परिजनों से बातचीत किया था। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय भी हरिओम के फतेहपुर स्थित आवास पर गए थे। अब कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल हरिओम के परिजनों को आर्थिक मदद देना चाहता है। आर्थिक मदद देने के लिए वे शनिवार को रायबरेली जा रहे थे। पुलिस ने रोक लिया।

पुलिस इको गार्डन ले जाना चाहती थी। ऐसे में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में सभी पदाधिकारी पार्टी कार्यालय के सामने धरने पर बैठ गए। इस दौरान पुलिस ने अजय राय को हिरासत में लिया है।

महाराष्ट्र में मुआवजे पर सियासत : उद्धव बोले- किसानों के साथ सबसे क्रूर मजाक, एकनाथ शिंदे बोले- घड़ियाली आंसू..

मुंबई । महाराष्ट्र में हाल ही में आई भारी बारिश और बाढ़ के कारण किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। ऐसे में अब राय सरकार द्वारा घोषित राहत पैकेज पर सियासत में गर्माहट सातवें आसमान पर पहुंच गई है। एक ओर जहां शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राय सरकार के मुआवजे को इतिहास का सबसे बड़ा मजाक बताया है। तो वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे पर पलटवार करते हुए उनकी संभाजीनगर में हुई रैली और बयान को घड़ियाली आंसुओं का तमाशा करार दिया।

मुआवजे की राशि इतिहास का सबसे बड़ा मजाक- ठाकरे

संभाजीनगर में एक रैली को संबोधित करते हुए शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख ने राय सरकार पर किसानों के मुआवजे को लेकर जमकर निशाना साधा। उन्होंने राज्य सरकार के मुआवजे को इतिहास का सबसे बड़ा मजाक बताते हुए कहा कि अगर सरकार ने किसानों के लिए पूर्ण कर्जमाफी की घोषणा नहीं की, तो किसान सड़कों पर उतरेंगे। इस दौरान ठाकरे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा। उन्होंने पीएम मोदी के हाल ही में किए गए महाराष्ट्र दौरे का जिक्र करते हुए कहा कि वे हाल ही में महाराष्ट्र आए लेकिन किसानों के मुद्दे पर एक शब्द नहीं बोले। उन्होंने सवाल उठाया कि जब किसानों की जिंदगी उजड़ गई है, तब सरकार में बैठे लोग चुप क्यों हैं।

एकनाथ शिंदे ने किया पलटवार

वहीं बयानबाजी का बाजार ज्यादा गर्म तब हो गया जब उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे के संभाजीनगर रैली में दिए गए बयानों को लेकर आड़ेहाथ लिया। शिंदे ने उद्धव ठाकरे पर पलटवार करते हुए उनकी रैली को घड़ियाली आंसुओं का तमाशा करार दिया। शिंदे ने कहा कि ठाकरे सत्ता से बाहर होने के बाद किसानों के दर्द का दिखावा कर रहे हैं।

शिंदे ने राहत पैकेज का किया जिक्र

शिंदे ने कहा कि जब खेत, घर और मवेशी सब बर्बाद हो गए, तब महायुति सरकार ने पूरे राय में दौरा किया और तय किया कि एनडीआरएफ के नियमों के बावजूद किसानों को तुरंत राहत दी जाएगी। इसके साथ ही शिंदे ने महाराष्ट्र सरकार की ओर से घोषित 31,628 करोड़ रुपये के राहत पैकेज का जिक्र करते हुए कहा कि किसानों के खातों में दिवाली से पहले 10,000 रुपये जमा कराए गए है। उन्होंने कहा कि जिन किसानों की फसलें बर्बाद हुई हैं, उन्हें 48,000 रुपये प्रति हेक्टेयर तक और मनरेगा के तहत 3.47 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर तक की सहायता मिलेगी। शिंदे ने कहा कि महायुति सरकार नारे नहीं, समाधान देती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के समर्थन से राय और केंद्र मिलकर काम कर रहे हैं ताकि कोई भी किसान पीछे न छूटे।

बिहार एनडीए में सीट बंटवारे पर सस्पेंस! कुशवाहा बोले- अफवाहों पर ध्यान न दें, अभी बात पूरी नहीं

पटना। राष्ट्रीय लोक मोर्चा (आरएलएम) के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने शनिवार को सोशल मीडिया पर अफवाहों के फैलने के बाद स्पष्ट किया कि दो चरणों में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव के लिए (सीटों के बंटवारे) पर बातचीत अभी पूरी नहीं हुई है। पहला चरण 6 नवंबर को और दूसरा चरण 11 नवंबर को होगा। मतगणना 14 नवंबर को होगी। शनिवार को एक्स इन हिंदी पर एक पोस्ट में कुशवाहा ने आगाह करते हुए कहा, अफवाहों पर ध्यान न दें। बातचीत अभी पूरी नहीं हुई है। रुकिए...! मुझे नहीं पता कि मीडिया में खबरें कैसे चल रही हैं। अगर कोई खबर प्लांट कर रहा है, तो यह धोखा है, विश्वासघात है। आप सभी इसी तरह सतर्क रहें। इस बीच, बिहार भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने शुक्रवार को कहा कि सीट बंटवारे का मामला सुलझ गया है और भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व शनिवार और रविवार को उम्मीदवारों के नामों की घोषणा करेगा। मीडिया से बात करते हुए, जायसवाल ने कहा कि दिल्ली में भाजपा ने सीट बंटवारे के लिए तीन दिवसीय चुनाव समिति की बैठक की और इसके लिए एक पैनल का गठन किया गया। भाजपा एक राष्ट्रीय पार्टी है और केंद्रीय नेतृत्व केंद्रीय चुनाव समिति और केंद्रीय संसदीय बोर्ड के माध्यम से उम्मीदवारों का चयन करता है। उन्होंने कहा कि सीटों के बंटवारे का मामला सुलझ गया है। कल और परसों दिल्ली में उम्मीदवारों का चयन और घोषणा की जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि केंद्रीय संसदीय बोर्ड उम्मीदवारों के नामों की घोषणा करेगा। उन्होंने कहा, सीटों के बंटवारे की घोषणा कल की जाएगी। यह आगामी चुनावी मुकाबला भाजपा और जनता दल (यूनाइटेड) (जेडी(यू)) के नेतृत्व वाले एनडीए और राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाले इंडिया ब्लॉक के बीच होगा।

भौंकने वाले कुत्ते...ओवैसी को नीतेश राणे की खुली धमकी

मुंबई ।

अहिल्यानगर के मुकुंदनगर स्थित सीआईडी ग्राउंड में एआईएमआईएम सांसद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की जनसभा हुई। इस बैठक में एमआईएम नेता वारिस पठान ने भाजपा नेता और मंत्री नितेश राणे पर हमला बोला। वारिस पठान ने मंत्री नितेश राणे को धमकी देते हुए कहा था आप दो पैरों पर आएंगे और स्ट्रेचर पर जाएंगे। मंत्री नितेश राणे ने इसका जवाब दिया है। कल की सभा अहमदनगर में नहीं, अहिल्यानगर में हुई थी। भौंकने वाले कुत्ते काटते नहीं। वे अहिल्यानगर में घूम रहे थे। वे कहते है कि वे कानून-व्यवस्था में विश्वास रखते हैं, लेकिन वे अहिल्यानगर नाम में विश्वास नहीं रखते, वे औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजीनगर करने में विश्वास नहीं रखते। राणे ने कहा कि क्या ये पाकिस्तान है? क्या ये शरिया है? जिनके विचारों ने पिलावल को जन्म दिया, वो भारत की आजादी के खिलाफ थे। एक सरकार के तौर पर हमें ये देखना होगा कि हमें आपकी बैठकें करनी चाहिए या नहीं। नितेश राणे ने जवाब देते हुए कहा है कि हरे सांप हिल गए है, हिंदुत्व की सरकार है। अगर माहौल बिगाड़ने की कोशिश हुई तो सरकार को भी सोचना पड़ेगा कि सभा की अनुमति देनी है या नहीं। पैगम्बर साहब कुरान पर बोलते हुए भड़क जाते हैं। जब तुम हमारी देवियों के हाथ तोड़ते हो, तो क्या हम बोलना नहीं चाहते? अगर आप हर जगह आई लव मोहम्मद के पोस्टर लगाकर हमें धमकाते हैं, तो हमें अपनी तीसरी आंख खोलने पर मजबूर मत कीजिए। सच्चा सनातनी हिंदू वह है जो अंबेडकर को मानता है। शिवशक्ति वह है जो भीमशक्ति को मानता है। नितेश राणे ने कहा कि वे शरिया लाना चाहते हैं, वे अंबेडकर को नहीं मानते। हिंदुत्व कार्यकर्ताओं के रूप में, हम पजामे का फंदा खोलना जानते हैं। उन्होंने रजाकारों के इतिहास का हवाला दिया। हमें मुंह खोलने पर मजबूर मत करो। तो वारिस पठान की चुनौती पर नितेश राणे ने कहा, जगह और समय बता दो, या मस्जिद चुन लो, धमकी मत दो, तुम जानते हो नितेश राणे क्या है। ये नसबंदी करने वाले बदमाश होंगे, ये लोग बस भौंकते है। हम राय का माहौल खराब नहीं करना चाहते। हमारी सरकार सभा की इजाजत दे रही है, इसलिए आप बोल सकते है, वरना आपको मस्जिद के लाउडस्पीकर से बोलना पड़ता। जब मूर्ति का अपमान हुआ था, तब AIMIM ने प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया?